

CS



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 29, 1992/फाल्गुन 10, 1913

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 29, 1992/PHALGUNA 10, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1992

फा.सं. 15/71—बी(डी)/91 :—बजट (1992-93)

वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह का भाषण :—

भाग 'क'

महोदय,

मैं वर्ष 1992-93 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

2. यह राजकोषीय वर्ष जो अब समाप्त होने वाला है, हर दृष्टि से एक कठिन वर्ष रहा है। यह वर्ष एक संकटपूर्ण और संकट की व्यवस्था करने का वर्ष रहा है। यह एक महान आर्थिक चुनौतियों और साहसिक नए कदम उठाने का वर्ष भी रहा है।

3. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि आठ महीने पहले जब नई सरकार ने कार्यभार संभाला था, हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी जो ढहने के कगार पर थी। मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही थी। भुगतान संतुलन की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। विदेशी मुद्रा का प्रारक्षित भण्डार मुश्किल में दो सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त था। विदेशी वाणिज्यिक बैंकों ने भारत को उधार देना बन्द कर दिया था। भारतीय मूल के अनिवासी भारतीय अपनी जमाओं को वापस ले रहे थे। विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण बड़े पैमाने पर आयात सीमित हो गए थे, जिनकी वजह से पिछले वर्षों की तीव्र औद्योगिक प्रगति रुक गई थी और मई, 1991 के बाद से उनमें नकारात्मक वृद्धि दर पैदा हो गई थी।

4. ऐसी विकट परंपरा हमें विरासत में मिली थी।

5. हमारी पहली और तात्कालिक चुनौती, इस गिरावट को रोकने और भारत की विश्वसनीयता, देश और विदेश दोनों ही स्थानों पर, फिर से कायम करने की थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहायताओं में चूक से बचने के

लिए तत्काल उपाय करने थे तथा अल्पावधि में अर्थव्यवस्था में बृहत्-आर्थिक संतुलन कायम करने के लिए भी कदम उठाने थे, ताकि मुद्रास्फिति पर काबू पाया जा सके और भुगतान संतुलन के घाटे को प्रबन्धकीय स्तर तक कम किया जा सके। हमारा मध्यावधिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था को एक उच्च और स्थिर विकास के मार्ग पर फिर से वापस लाना था।

6. इन उद्देश्यों के अनुसरण में नई सरकार ने बहुत से उपाय किए। हमने विदेशी भुगतानों में चूक से बचने के लिए, जो अत्यंत विनाशकारी होता, तात्कालिक उपाय किए। पिछली सरकार ने विदेश में अस्थायी रूप से नकदी जुटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित सोने के एक भाग का उपयोग करने का पहले ही निर्णय ले लिया था। हमने इस निर्णय को उलटना उचित नहीं समझा, किन्तु हमने सोने को शीघ्र से शोध वापस लेने का वायदा किया और हमने अपना वायदा पूरा भी किया। हमने राजकोषीय घाटे को, जो पिछले वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया था, कम करने के प्रयास द्वारा बृहत्-आर्थिक संतुलन फिर से कायम करने की प्रक्रिया शुरू की। हमने संरचनात्मक सुधार करने का, जिसमें भारतीय उद्योग की कार्यकुशलता, उत्पादकता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के उद्देश्य से व्यापार नीति और औद्योगिक नीति में नए उपाय अपनाना सम्मिलित था, एक मध्यावधिक कार्यक्रम भी शुरू किया। हमारा दीर्घावधिक उद्देश्य उत्पादन की एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जो ध्रम प्रधान हो और जिससे उत्पादक उच्च आय उपाजन में अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा हों तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच आय और सम्पत्ति के बीच असमानताओं में कमी आए।

7. संकटपूर्ण वर्ष में उत्पादन में हानि होनी ही थी और वर्ष 1991-92 में यही हुआ। खरीफ मौसम में कृषि उत्पादन लक्ष्य से कम रहा किन्तु रबी की फसल की संभावनाएं अच्छी हैं। गंभीर आयात संकुचन और कठिन ऋण स्थितियों के कारण औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तथापि, आधारभूत क्षेत्रों में, जो भारी औद्योगिक प्रगति का मूल आधार है, काफी अच्छी प्रगति हुई है। मैं आशा करता हूं कि 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद में कुल लगभग 2.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। मुझे 1992-93 में और भी विशिष्ट सुधार होने की तथा 1993-94 में ऊंची दर फिर से प्राप्त कर लेने की उम्मीद है। तथापि, यह पुनरुत्थान केवल तभी हो सकता है, यदि हम इस वर्ष शुरू किए गए स्थिरीकरण और आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को बिना किसी हिचकिचाहट के जारी रखें।

8. स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के उपाय कभी भी कठिनाई रहित अथवा तुरंत नहीं होते हैं, विशेष रूप से जबकि हम ऐसे असंतुलों और संरचनात्मक दृढ़ताओं से निपट रहे हों, जो अनेक वर्षों के दौरान बने हों। कम से कम तीन वर्ष तक कठिन प्रयास करना पड़ेगा ताकि अर्थ-व्यवस्था एक तीव्र और स्थिर प्रगति के मार्ग पर फिर से

वापस आ सके। मितव्ययता के प्रति दृढ़ वचनबद्धता, श्रेष्ठता को बनाए रखना और आम लोगों के लाभ के लिए कार्य-कुशलता तथा उत्पादकता को प्रोत्साहित करना, इस प्रयास का अभिन्न अंग होंगे। अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए हमारे लोग निर्वीर उन्मोक्तवाद और पश्चिम के समृद्ध देशों की व्यर्थपूर्ण जीवनशैली की नकल नहीं कर सकते। आश्चर्यपूर्ण उपभोग को कारगर ढंग से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। कृपायत के गुणों पर बल दिया जाना चाहिए। संपदा के मालिकों को, जैसा कि गांधी जी कहा करते थे, अपने आपको समाज के एक द्रुसी के रूप में समझना चाहिए। हम संरचनात्मक सुधार और समायोजन को स्थगित नहीं कर सकते, किन्तु हमें यह सुनिश्चन करना चाहिए कि समायोजन का बोझ हमारे समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों पर अधिकतम संभव सीमा तक कम से कम पड़े। हम कठिन और असमनल तराई के रास्ते से गुजर रहे हैं, जहां कोई भी कार्य जोखिम रहित नहीं है और सफलता सदा ही तुरंत मिलने वाली नहीं है। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए हमें धैर्य, सन् प्रयत्न और राष्ट्रीय सामान्यसज्ज की जरूरत है।

9. कुछ लोगों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि सुधार कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दशरे पर तैयार किया गया है। हम दोनों संस्थाओं के संस्थापक सदस्य हैं और अपने कार्यक्रमों के समर्थन में सहायता आवश्यक होते पर हमें उनसे उधार लेने का अधिकार है। उधारकर्ता के रूप में उन्हें ऋणों का वापसो अदायगी का हमारी क्षमता के बारे में अपने आपको आश्वस्त होना है और इसी वजह से शर्त का बात बोच में आता है। उधार लेने वाले सभी देश उन कार्यक्रमों की सक्षमता के संबंध में, जिनके लिए सहायता का मांग को जाती है इन संस्थाओं के साथ चर्चाएं आयोजित करते हैं। हमने भाएसा हा चर्चाएं को हैं। शर्तों को सोमा मांगो गई सहायता को राशि और किस्म पर निर्भर करता है। तथापि मैं यह स्पष्ट रूप से भता देना चाहता हूं कि हमने जो शर्तें मंजूर की हैं, वे उन सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से अधिक कुछ नहीं दर्शाती जिनका उल्लेख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को भेजे गए मेरे आशय पत्रों में किया गया है और वे पूर्णतः हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हैं। सुधार कार्यक्रम का अधिकांश भाग हमारी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र पर आधारित है। प्रभुसत्ता को तो बात दूर है सरकार के लिए अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कोई समझौता करने का प्रश्न हा नहीं उठता।

10. यद्यपि हमारी नीतियों के पूरे परिणाम प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा तथापि मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि हमने आठ महीने का इस थोड़ा सा अवधि में भी काफी प्रगति की है। हमने भारत को विश्वसनीयता को फिर से कायम करने और अर्थव्यवस्था को वित्तीय संकट में फंसने से बचाने के लिए अपना सबसे तात्कालिक उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। हमारे विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डार

फिर से लगभग 11,000 करोड़ रुपए तक पहुँच गए हैं। अनिवार्यता भारत में अब अपनी जमा राशियों को वापस नहीं ले रहे हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के साथ, वर्तमान वर्ष में भुगतान संतुलन के समर्थन हेतु तुरंत संवितरण निधियाँ प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक प्रबंध संपन्न किए हैं।

11. मुद्रास्फाति एक गंभीर और ऐसी समस्या बन गई है, जिसे हम सर्वोच्च प्राथमिकता देने हैं, क्योंकि मुद्रास्फाति से निर्धन व निश्चित आय वाले लोगों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जून, 1991 में जब हमारा सरकार सत्ता में आई, मुद्रास्फाति तेज। ये बढ रहा था और अगस्त, 1991 में मुद्रास्फाति का वार्षिक दर 16.7 प्रतिशत के शिखर पर पहुँच गई था। उसके बाद मुद्रास्फाति का दर घटकर लगभग 12 प्रतिशत तक आ गई है, किन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब भी यह काफी अधिक है। हम मुद्रास्फाति को नियंत्रण में लाने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ हैं। यहाँ कारण है कि 1991-92 के बजट में राजकोषीय अनुशासन का आवश्यकता पर बल दिया गया था। मुझे विश्वास है कि हम 1992-93 में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखेंगे और यदि हमें कामतों को नियंत्रण में लाना है तो इसका पालन करते हुए रहना चाहिए, तथा मुद्रास्फाति दर आने वाले राजकोषीय वर्ष में काफी कम हो सकेगा।

12. विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भंडारों में सुधार होने से मुद्रास्फाति के साथ संघर्ष करने को हमारी क्षमता काफी बढ़ा है। इसी वजह से हम आयातों पर प्रतिबंधों को शिथिल करने में समर्थ हुए हैं, जो पिछले वर्ष लगाए थे और इस प्रकार आगामी महानों में आवश्यक आयातों का लगभग सामान्य उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। इससे उत्पादन में मदद मिलेगी और स्फातिकार दबावों में कमी आएगी। संतोषजनक भण्डारों की स्थिति में सरकार का कमियों से निपटने और स्फातिकार दबावों पर काबू पाने के लिए अनिवार्य मदों के अतिरिक्त आयात के वित्तपोषण के लिए और अधिक लचाला रखे अनुरोधों में मदद मिला है।

13. सरकार कामतों के संबंध में पूर्ण जागरूक रहेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग, मुद्रास्फाति का सामना करने और विशेष रूप से जनसंख्या के निर्धन वर्गों को ऊँचा कामतों और अभाव से संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष पहला जनवरी को देश के लगभग 1700 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में नवोद्भूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने का घोषणा की है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ हैं कि खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुएँ निर्धनों और कम भुविधा प्राप्त लोगों तक पर्याप्त मात्रा में और वहनीय कामतों पर पहुँचे।

14. मुद्रास्फाति के बाद अस्वास्थ्य में हमारा प्रमुख समस्या भुगतान संतुलन के प्रबंध की है। हमने गिरावट को

रोक लिया है और कुछ लचालापन प्राप्त कर लिया है, किन्तु अपनी विदेशी अदायगी संबंधी स्थिति में सतत रूप से सुधार करने के लिए हमें और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ व्यापार में आए व्यवधान के कारण मुख्य रूप में और विश्व बाजारों में मन्दा की स्थितियों के कारण भी इस वर्ष हमारा निर्यात आय बुरा तरह प्रभावित हुई है। परिणामतः हम अपनी सामान्य आयात आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने में समर्थ नहीं हो सके हैं।

15. कुछ व्यक्ति यह दर्शाते हैं कि भुगतान संतुलन का समस्या के समाधान के लिए हमें केवल इस बात को आवश्यकता है कि हम अपने आयातों को कम कर दें। मैं बताना चाहूँगा कि आयातों का पहले ही अत्यंत संकुचन किया जा चुका है और इनका और अधिक संकुचन करने से विकास और रोजगार दोनों पर ही गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। अनावश्यक उपभोगिता वस्तुओं का आयात अवश्य ही हतोत्साहित किया जाता रहना चाहिए। तथापि, हमें यह स्वाकार करना चाहिए कि हमारा भुगतान संतुलन का समस्या का मात्र स्थायी समाधान आयात के संकुचन में नहीं है बल्कि निर्यात को तेजा से बढ़ाने में है। एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन तथा अन्य औद्योगिक निर्यातों का तथा साथ ही आधुनिक औद्योगिकों के समावेश वाला उच्च गुणवत्ता वस्तुओं के अधिकाधिक मात्रा में आयात करने का आवश्यकता है। इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के महत्व को नकारना नहीं है, बल्कि एककृत विश्वव्यापी बाजारों का आज का दुनिया में आत्मनिर्भरता को मात्र आयात-निर्भरता को कम करके और अर्थव्यवस्था को विश्व से अलग रख कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस मार्ग पर चलने के लिए केवल और अधिक आयात नियंत्रणों को अपनाना होगा और ऐसा करने से अकार्यकुलता तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके फलस्वरूप एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जिसमें भारतीय उद्यमियों को वह लचाला रख प्राप्त नहीं हो सकेगा, जिसका उन्हें विश्व बाजारों में अन्य विकास-शील देशों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए आवश्यकता है। निर्यात करने का परिणामी अयोग्यता से वस्तुतः हम बाहर विश्व पर कम निर्भर होने का वज्राय अधिक निर्भर हो जाएंगे। आत्मनिर्भरता वाला अर्थव्यवस्था को हमारे कल्पना, एक ऐसी अर्थव्यवस्था का होना चाहिए जो विदेशी सहायता जैसे बाह्य कृत्रिम साधनों पर अनुचित निर्भरता के बिना निर्यात के माध्यम से अपनी सभी आयात आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस महान मदद को मेरा मुझा है कि यह वस्तुतः आत्मनिर्भरता का बड़ा कल्पना है जो हमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तराधिकार में मिला है और जैसा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बताया गया था, जिसे आज के विश्व में वास्तविकताओं में बदला गया है।

16. पिछले वर्ष नई व्यापार नीति लागू करते समय सरकार ने यह उल्लेख किया था कि हमारा यह ध्येय रहेगा कि हम चालू खाने पर रुपए की परिवर्तनीयता की दिशा में

भागों बढ़ें। परिवर्तनीयता की उपलब्धि आर्थिक मजबूती और सच्ची आत्मनिर्भरता का एक चिह्न है। आंशिक परिवर्तनीयता की एक नई प्रणाली लागू करके हम अब इस दिशा में अग्रगण्य महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार हैं। नई प्रणाली का उद्देश्य हमारे निर्यात को एक जोरदार सबल प्रदान करना तथा एक सक्षम आयात प्रतिस्थापन प्रदान करना है। इससे नौकरशाही नियंत्रणों की गुंजाइश में और कमी आएगी, जिससे अकार्यकुशलता और भ्रष्टाचार दोनों को बढ़ावा मिलता है। इससे विदेशी मुद्रा में गैर-कानूनी कारोबार के लिए प्रोत्साहन में भी बहुत कमी आएगी। नई प्रणाली के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की सभी प्रेषणाओं को, चाहे वे वस्तुओं अथवा सेवाओं के निर्यात के जरिए अथवा प्रेषणाओं के जरिए अर्जित हों, निम्नलिखित ढंग से रूप में बदला जाएगा : प्रेषित विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग सरकारी विनियम दर पर बदला जाएगा। तथा शेष 60 प्रतिशत बाजार निर्धारित दर पर बदला जाएगा, सरकारी विनियम दर पर समर्पित विदेशी मुद्रा अनिवार्य आयातों, जैसे कि पेट्रोलियम और तेल उत्पादों, उर्वरकों, रक्षा और जीवन रक्षक औषधियों की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा। कच्चे माल, कलपुर्जों और साथ ही पूंजीगत वस्तुओं के सभी अन्य आयात को खुले सामान्य लाइसेंस पर मुक्त रूप से आयात योग्य बना दिया जाएगा, किन्तु इन आयातों के लिए विदेशी मुद्रा बाजार से प्राप्त करनी होगी। कच्चे माल, कलपुर्जों और पूंजीगत वस्तुओं की एक विनिर्दिष्ट "नकारात्मक सूची" होगी, जिनका आयात लाइसेंसों के विरुद्ध ही करना जारी रहेगा। उपभोक्ता वस्तुओं के लिए आयात नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो प्रतिबंधित रहेगी। यात्रा ऋण, परिशोधन अदायगियों, लाभशों, रायल्टियों व अन्य प्रेषणाओं सहित गैर-सरकारी खातों पर अन्य अदायगियों के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा भी बाजार दर पर प्राप्त करनी होगी।

17. नई प्रणाली एग्जिमस्क्रिप्स की प्रणाली का स्थान लेगी। प्रत्येक निर्यात लेनदेन के लिए एग्जिमस्क्रिप जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नई प्रणाली बैंकों के माध्यम से संचालित होगी। एग्जिमस्क्रिप्स पर प्रीमियम के स्थान पर निर्यातकों को विदेशी मुद्रा बाजार में उनकी आय के 60 प्रतिशत भाग पर प्रीमियम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन अब विदेशों में हमारे कामगारों से प्रेषणाओं पर भी उपलब्ध होंगे। इस बात की कोई वजह नहीं है कि हमारे कामगारों को, जो विदेश में अपने कठिन परिश्रम के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, इस समय वस्तुओं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यातों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों से वंचित रखा जाए। मैं विदेशों में कार्य कर रहे केरल और अन्य राज्यों के लोगों का अभिनन्दन करता हूँ। आज मैंने जो घोषणा की है वह उन लोगों द्वारा भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन में किए जाने वाले शानदार योगदान के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक मात्र है।

18. इन परिवर्तनों के साथ हम व्यापार नीति के सरलीकरण, लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने और संबद्ध नौकरशाही की बेरी और बहुत सी मर्शों के संबंध में अकार्यकुशलताओं को दूर करने का प्रमुख उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे। हम, भुगतान संतुलन के एक बड़े भाग का प्रबंध करने के लिए भी एक स्व-संतुलनकारी पद्धति लागू कर लेंगे। आयात की कुल मात्रा स्वतः ही स्वदेशी मुद्रा की उपलब्ध मात्रा द्वारा विनियमित होगी। विदेशी मुद्रा के अभाव से प्रीमियम परिलक्षित होगा, जो निर्यातकों को व उन व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो प्रेषणाएं भेजते हैं और इस प्रकार इस प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक तैयारगुदा प्रोत्साहन की व्यवस्था होगी। नई विदेशी मुद्रा प्रणाली के ब्योरे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए जा रहे हैं। व्यापार नीति में परिवर्तन संबंधी अधिसूचनाएं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही हैं।

19. विदेशी मुद्रा का गैर-कानूनी माध्यमों से भेजने का एक कारण सोने का गैर-कानूनी आयात है। अब समय है कि हम स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करने और सोने के आयात को कानूनी बनाने के लिए साहसिक कदम उठाएं। सरकार का प्रस्ताव, वापस लौटने वाले भारतीयों तथा अनिवामी भारतीयों को प्रति यात्री साधारण आयात शुल्क पर 5 फीसद तक सोने के आयात की अनुमति देने का है, बशर्ते की सोने और आयात-शुल्क दोनों का वित्तपोषण विदेश में अर्जित विदेशी मुद्रा से किया जाए।

20. इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने यह मुझाव दिया है कि सरकार को स्वर्ण बांड जारी करने चाहिए, जिनसे सरकारी भण्डारों को पूरक बनाने में साधारण नागरिकों के निष्क्रिय पड़े स्वर्ण संसाधनों को जुटाने में मदद मिलेगी। मैंने संसद में बताया था कि इस पर अभी विचार किया जाना चाहिए, जब हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हो जाए और अर्थव्यवस्था के प्रबंध में सरकार की क्षमता में पर्याप्त विश्वास पैदा हो जाए। अब यह प्राप्त हो गया है। हमारे भण्डार काफी अधिक हैं और उन्हें पूरक बनाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु मैं नहीं समझता कि देशभक्त नागरिकों को भारत की अर्थ-व्यवस्था के विकास में अपना थोड़ा भी अंशदान करने से क्यों वंचित रखा जाए। मेरा प्रस्ताव एक ऐसी स्कीम शुरू करने का है, जिसके अंतर्गत नागरिक स्वर्ण के बदले बांड प्राप्त कर सकते हैं। इन बांडों की अवधि पांच से सात वर्ष तक की होगी और इन्हें सोने की वापसी अथवा समकक्ष मूल्य द्वारा, धारक के विकल्प पर, भुनाया जा सकेगा। इन पर थोड़ा ब्याज मिलेगा जिस पर आयकर लागू नहीं होगा। ये बांड सम्पत्ति कर और दान कर से भी मुक्त होंगे। एक और प्रोत्साहन के रूप में ऐसे बांडों के धारकों से स्वर्ण-धारण के खान के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इन्हीं के अनुसार एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

21. नई औद्योगिक नीति की एक नई बात विदेशी निवेश की प्रति एक नए दृष्टि-कोण की है, जो हमारे प्रौद्योगिकीय स्तरों को उन्नत करने, हमारे उद्योगों को विश्व प्रतियोग्यवस्था के साथ संमेलित करने और ऋण-भित्त संसाधनों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार का प्रस्ताव उन महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों में विदेशी निवेश को सक्रियता के साथ प्रोत्साहित करने का है, जहाँ क्षमताएं अपर्याप्त हैं और निवेश की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। विद्युत् क्षेत्र में विदेशी निवेश सहित निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की नीति पहले ही घोषित की जा चुकी है। एक अन्य क्षेत्र जो हमारे भावी विकास और भुगतान संतुलन के प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण है, वह हाइड्रो-पावर क्षेत्र है। सरकार पहले ही यह घोषित कर चुकी है कि खोज और विकास दोनों ही क्षेत्रों में, जिसमें विद्यमान क्षेत्रों का विकास भी शामिल है, संयुक्त उद्यमों की अनुमति होगी। सरकार, तेल और गैस के उत्पादन, परिशोधन और विपणन में विदेशी निवेश सहित निजी निवेश के प्रस्तावों का स्वागत करेगी, ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की विकास क्षमता को दृष्टान्त बनाया जा सके।

22. कभी-कभी यह चिन्ता व्यक्त की जाती है कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की हमारी नीति से भारतीय उद्योगों को हानि पहुंचेगी और इससे हमारी प्रभुसत्ता खतरे में पड़ सकती है। ये भय निरापद हैं। हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भय से स्थायी रूप से ग्रस्त नहीं रहना चाहिए, जैसा कि पिछले 300 सालों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी शक्तों पर विदेशी निवेशकों के साथ निपटने में सक्षम है। भारतीय उद्योग ने भी अपनी विकास क्षमता प्राप्त कर ली है और अब यह एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जबकि यह विदेशी निवेश के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों ही कर सकता है। पूरे विश्व में यह प्रवृत्ति विद्यमान है और हम इससे बचकर नहीं रह सकते। सदन इस बात से आश्वस्त हो सकता है कि हमारे पास पर्याप्त नीति-विषयक उपाय हैं, जिनसे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि विदेशी हकिवटी वाले उद्यम हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करें।

23. औद्योगिक नीति के प्रति नए दृष्टिकोण में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जैसे विनियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी वाली कंपनियों और साथ ही अनिवासी भारतीयों पर काफी मात्रा में विस्तृत प्रशासनिक नियंत्रण लागू किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में विदेशी पूंजी वाली भारतीय कंपनियों और भारत लौटने वाले अनिवासी भारतीयों पर लागू, इनमें से अनेक नियंत्रणों से सामान्य रूप से छूट प्रदान करके प्रक्रिया को उदार बना दिया है। कुछ अन्य प्रतिबंध हैं जो भारतीय कंपनियों और भारतीय निवासियों को पूर्व अनुमति के बिना विदेश में कंपनियों के साथ विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक संबंध कायम करने से रोकते हैं। ये व्यवस्थाएं आज की प्रतियोग्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं; जबकि

भारतीय व्यापार को विदेश में अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ व्यापक रूप से व्यवहार करता होगा, जिसके लिए शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है। सरकार का प्रस्ताव विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में व्यापक शोधन करने का है ताकि इसे नई नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

24. पिछले वर्ष अपने वजट भाषण में मैंने वित्तीय क्षेत्र सुधार के महत्व का जिक्र किया था और वित्तीय प्रणाली के संबंध में एक समिति स्थापित करने की घोषणा की थी। नरसिम्हम समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे संसद में रख दिया गया है। समिति ने बैंकिंग प्रणाली द्वारा विभिन्न दिशाओं में की गई प्रगति की यद्यपि प्रशंसा की है तथापि समिति ने कम लाभप्रदता घटिया पोर्टफोलियो गुणवत्ता और डूबते ऋणों के लिए अपर्याप्त व्यवस्था के कारण प्रणाली की वित्तीय स्थिति में गिरावट के कारण उत्पन्न गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। समिति ने बैंकिंग के सभी पहलुओं को शामिल करने हुए, जिनमें बेहतर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को लागू करना, डूबते ऋणों के लिए बेहतर व्यवस्था करना, निर्देशित उधार और संबद्ध व्याज दर संरचना संबंधी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना शामिल है, सुधार के लिए व्यापक सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशों में एक अधिक कारगर और प्रतियोगी बैंकिंग प्रणाली जिसमें निजी क्षेत्र के लिए एक बड़ी भूमिका सम्मिलित है, लागू करने पर बल दिया गया है। अनेक सिफारिशों को तेजी से लागू किया जा सकता है। अन्यो पर और विचार किए जाने की आवश्यकता है। सरकार का प्रस्ताव समिति की सिफारिशों को एक क्रमिक ढंग से लागू करने का है।

25. नरसिम्हम समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में पहले कदम के रूप में सरकार ने सांविधिक नकदी अनुपात (एल.एल.आर.) में, जिसने इस समय अपेक्षाकृत कम आमदनी वाली सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक निधियों की बड़ी मात्रा रुकी हुई है तदनुसार वाणिज्यिक बैंकों की वृद्धिकारी धरेलू देयताओं पर सांविधिक नकदी अनुपात को वर्ष 1992-93 से 38.5 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है। यह कमी राजकोषीय घाटे में प्रस्तावित कमी के अनुरूप है जिससे वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेने की केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता में कमी आएगी। इससे कृषि और उद्योग को ऋण देने के लिए बैंकों के पास निधियां उपलब्ध हो सकेंगी। राज्यों के बाजार उधारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक सक्रिय बाजार विकसित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं जिससे सरकारी भविष्य में बैंकों से सांविधिक उधार पर कम निर्भर होगी।

26. मुद्रास्फीति की दर में आई गिरावट को देखते हुए बैंकों द्वारा वाणिज्यिक अग्रिमों पर ली जाने वाली व्याज दरों के संबंध में राहत प्रदान करना संभव है। भारतीय रिजर्व

बैंक वाणिज्यिक अग्रिमों पर व्याज दरों के न्यूनतम स्तर में एक प्रतिशत बिंदु की कटौती की अलग से अधिमूचना जारी कर रहा है।

27. वित्तीय क्षेत्र सुधार में पूंजी बाजारों का सुधार भी शामिल है, जो जनता से संसाधन जुटाने और आवंटन में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। पिछले वर्ष मेरे बजट भाषण में घोषित अनेक उपायों को कार्यान्वित किया जा चुका है। भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड की अब सांविधिक आधार पर स्थापना की जा चुकी है। जैसे-जैसे हम अनुभव प्राप्त करेंगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड को, इसकी क्षमता में मजबूती लाने के उद्देश्य से, और अधिक अधिकार दिए जाएंगे। सरकार ने मार्गनिर्देश भी जारी किए हैं, जिनसे नई निजी क्षेत्र पारस्परिक निधियों का कार्य-चालन अधिशासित होगा। सरकार ने अच्छा पिछड़ा रिकार्ड रखने वाली कंपनियों को विदेश में निवेशकों को इक्विटी अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी करने तथा इन निर्गमों पर वही कर-लाभ देने की अनुमति प्रदान की है जो अपतटीय पारस्परिक निधियों के लिए उपलब्ध है। इससे देशज कंपनियों को विश्व पूंजी बाजार में उपलब्ध बड़ी मात्रा में इक्विटी निधियां जुटाने में मदद मिलेगी। हम विख्यात विदेशी निवेशकों को, जैसे कि पेंशन निधियों को, हमारे पूंजी बाजारों में, उपयुक्त कार्यप्रणालियों के साथ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इससे प्रबंध नियंत्रण समाप्त होने का कोई भय नहीं है, निवेश करने की अनुमति देने के उपायों पर भी विचार करेंगे।

28. वित्त मंत्रालय में पूंजी निर्गम नियंत्रक की भूमिका की, विशेष रूप से उभरते हुए औद्योगिक और वित्तीय परिदृश्य के संदर्भ में, समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। आज की बदलती हुई परिस्थितियों में पूंजी निर्गमों पर और साथ ही निर्गमों की कीमतों पर सरकारी नियंत्रण की प्रथा अप्रासंगिक हो गई है। इसलिए प्रीमियम निर्धारण सहित पूंजी निर्गमों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त करने का प्रस्ताव है। कंपनियों को बाजार तक सीधे ही पहुंचने की अनुमति होगी, बशर्ते कि निर्गम, प्रकटन तथा निवेशकर्ता के संरक्षण से संबद्ध अन्य मामलों से संबंधित प्रकाशित मार्गनिर्देशों के अनुरूप हों। सरकार इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक विधान लाने का प्रस्ताव कर रही है।

29. वर्ष 1991-92 का बजट प्रस्तुत करने समय मैंने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और आधुनिकीकरण की लागत का कामगारों पर अत्य-

धिक बोझ न पड़े, एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि स्थापित करने के सरकार के द्वाड़े की घोषणा की थी। इन निधि का उद्देश्य एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना था, जिससे प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के प्रतिकूल परिणामों से कामगारों को सुरक्षा प्राप्त होगी। सरकार ने अब इस निधि की स्थापना कर दी है। निधि के अंतर्गत, आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के फलस्वरूप कामगारों के पुनःप्रशिक्षण और पुनर्नियोजन की लागत वहन करने के लिए सहायता तथा साथ ही किसी औद्योगिक इकाई के पुनर्गठन द्वारा प्रभावित कामगारों को क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाएगी। सरकार का प्रस्ताव राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए आवश्यकता को पूरा करने के वास्ते बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से संपर्क करने का भी है। अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध होगी जिसका उपयोग निधि के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच स्कीमों के लिए किया जाएगा, जिनमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विशेष योजनाएं भी शामिल हैं। इस संदर्भ में, हम हस्त-शिल्प प्रौद्योगिकी के उन्नयन की एक योजना तैयार करेंगे जिसमें विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त हो। माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि सरकार औद्योगिक कण्ठता और संरचनात्मक सुधारों की समस्याओं से निपटते समय कामगारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ है।

30. कृषि हमारी राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है और आर्थिक विकास की कोई नीति हमारे देश में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि इसमें कृषि में रोजगार और उत्पादन की तीव्र गति सुनिश्चित न हो और जब तक हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नहीं बचल सेते तब तक अपने बढ़ते हुए ग्रामीण श्रमिक बल के लिए पर्याप्त रोजगार प्रदान करने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके लिए एक बहु-आयामीय नीति की आवश्यकता है। जिसमें भू-सुधारों का कारगर कार्यान्वयन और सिंचाई तथा नाली व्यवस्था-बड़ी मात्रा में निवेश, जल प्रबंध प्रणालियों में सुधार, भूमि-ह्रास पर नियंत्रण, ऋण प्रणाली को मजबूत बनाना और कृषि दिस्तार तथा अनुसंधान में सुधार करना शामिल है। चूंकि कृषि एक राज्य विषय है, इसलिए इस दिशा में अधिकांश प्रयास राज्य सरकारों को करने होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें इन मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगी। केन्द्र अपनी ओर से निरंतर निधिकरण और विभिन्न निर्धनता उन्मूलन योजनाओं के पुनर्गठन के प्रति, जो हमारी विकास नीति का एक प्रमुख अंग है, दृढ़-प्रतिज्ञ है।

31. विभिन्न प्रकार के कृषि व्यवसाय को समर्थन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार पैदा करने के लिए नवीन विचारों को समर्थन देने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक प्रयोगात्मक उपाय के रूप में सरकार का प्रस्ताव, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और आई.डी.बी.आई. द्वारा वित्तपोषित एक स्थायित्व निगमित डकार्ड के रूप में एक लघु कृषक-कृषि-व्यवसाय संघ स्थापित करने का है। संघ में अलग-अलग फसलों से संबंधित विभिन्न विकास बोर्डों तथा कृषि और कृषि-उद्योगों से संबंधित सरकारी क्षेत्र के निगमों, निजी क्षेत्र की कंपनियों, बैंकों, वैज्ञानिक संगठनों और कृषक संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संघ, आर्थिक कार्यकुशलता, पर्यावरणात्मक दृढ़ता और समाजिक समानता के सिद्धांतों पर कार्य करेगा तथा वर्ष 1992-93 में देश के विभिन्न भागों में, मिले-जुले उद्यमों और राज्य सरकारों तथा कृषक परिवारों की सक्रिय सहभागिता के आधार पर, 12 प्रमुख परियोजनाएं आयोजित करेगा। जैसे-जैसे हमें अनुभव होता जाएगा हम कार्यक्रम का विस्तार करने जाएंगे। हमें, अपने कृषि इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करना चाहिए जहां कृषि उद्यमों से न केवल अधिक लाभ प्राप्त होता है, बल्कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उत्पादक रोजगार और अधिक आय प्राप्त होनी है।

32. अब मैं वर्ष 1991-92 के संशोधित अनुमानों की चर्चा करूंगा। वर्ष 1991-92 में हमारा मुख्य बृहत्-आर्थिक लक्ष्य राजकोपीय घाटे को कम करना था, जिससे कि अर्थ-व्यवस्था में बृहत्-आर्थिक संतुलन की पुनः स्थापना की जा सके। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहे हैं।

33. 1991-92 के बजट अनुमानों में 113,422 करोड़ रुपए के कुल व्यय की व्यवस्था की गई थी। पिछले वर्षों के विपरीत, जबकि व्यय के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में काफी अधिक हो जाया करते थे, इस वर्ष यह 320 करोड़ रुपए के थोड़े से अंतर से कम रहे हैं। राजस्व पक्ष में, वर्ष की अधिकांश अवधि में अत्यधिक आयात संकुचन के कारण सीमाशुल्क राजस्व में, 3,760 करोड़ रुपए की भारी कमी हुई है लेकिन यह कमी उत्पाद शुल्क तथा आय कर की अधिक उगाहियों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गयी है, जिसके फलस्वरूप सकल कर राजस्वों में यह कमी 1,869 करोड़ रुपए की रह गई है। कर-भित्त राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां भी काफी अधिक हुई हैं। परिणामस्वरूप, कुल प्राप्तियां 106,070 करोड़ रुपए होने का अनुमान 105,703 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से अधिक है।

34. 1991-92 के संशोधित अनुमानों में बजटीय घाटा 70,032 करोड़ रुपए का है जो कि 7,79 करोड़

रुपए के बजट अनुमानों से कम है तथा 1990-91 की तुलना में, जब कि बजटीय घाटा 11,347 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, काफी कम है। संशोधित अनुमानों में राज-कोपीय घाटा, सभी ऋणों को भी हिसाब में लेने के बाद, 37,792 करोड़ रुपए का है। यह राशि 37,727 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों के लगभग समान है तथा 1990-91 के 44,650 करोड़ रुपए की राशि से बहुत कम है। इस प्रकार हम राजकोपीय घाटे को 1990-91 के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8.4 प्रतिशत में कम करके 1991-92 में लगभग 6.5 प्रतिशत तक लाने में सफल रहे हैं।

35. व्यय पक्ष में कड़ा अनुशासन लागू करके ही घाटे में यह कमी लाना संभव हो सका है। बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, कुछ अतिरिक्त व्यय संबंधी प्रावधान करने आवश्यक हो गए थे। इनमें सबसे उल्लेखनीय उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता हेतु अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता थी जो कि प्रारंभिक रूप से प्रस्तावित 40 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि को केवल 30 प्रतिशत तक रखे जाने संबंधी निर्णय तथा इस तथ्य के कारण भी उत्पन्न हुई कि आयातित उर्वरकों की क़य्या लागत बजट अनुमानों में अनुमानित राशि से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान की राशि, जो बजट अनुमानों में 4,000 करोड़ रुपए थी, संशोधित अनुमानों में उसे बढ़ाकर 4,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि यह राशि भी 1991-92 के लिए आर्थिक सहायता संबंधी सभी दावों के लिए पूरी नहीं बैठती है और कुछ राशि आगामी वर्ष में आगे चली जाएगी, जैसी कि एक सामान्य वाणिज्यिक प्रथा है। छोटे किसानों को संशोधन-पूर्व मूल्यों पर उर्वरकों की आपूर्ति करने की योजना के लिए संशोधित अनुमानों में 405 करोड़ रुपए को अलग व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

36. निर्गम मूल्य बढ़ाने में देरी होने के कारण, मुझे खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता हेतु बजट प्रावधान में 250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ी है। निर्गत संबंधी आर्थिक सहायता के लिए भी 550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है। यह आर्थिक सहायता 3 जुलाई, 1991 को समाप्त कर दी गई थी, लेकिन बकाया दावे मूल रूप से प्रत्याशित दावों से कहीं अधिक प्रतीत होते हैं। लेकिन अतिरिक्त व्ययों की इन मांगों को विभिन्न मंत्रालयों के स्वीकृत बजटों में होने वाली बचतों द्वारा प्रतिसंतुलित कर लिया गया है।

37. वर्ष 1991-92 में संसाधनों की कठिन स्थिति का प्रभाव आयोजना व्यय पर पड़ा। सकल संसाधन संबंधी कमी के कारण सरकार को केन्द्रीय योजना हेतु बजटीय समर्थन को सीमित रखना पड़ा तथा इस मद के लिए संशोधित अनुमान, बजट अनुमानों से 7 प्रतिशत कम है। इस

आंशिक कटौती के बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गये कि उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाएं इससे प्रभावित न हों तथा वास्तविक रूप से चल रही योजनाओं की वास्तविक प्रगति के अनुरूप धनराशि जारी करने की विनियमित करके इस कटौती को पूरा किया गया है। मुख्यतः विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की अधिक रुपया आवश्यकताओं के कारण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में 651 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई।

38. सदन को यह जानकारी हर्ष होगा कि हालांकि संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय सरकार का अपना व्यय बजट अनुमानों से कम है, तथापि करों के हिस्से तथा केन्द्रीय आयोजना सहायता के रूप में राज्यों को दिया जाने वाला कुल अंतरण बजट अनुमानों से 1,683 करोड़ रुपए अधिक है, इस प्रकार यह राशि, 1,365 करोड़ रुपये की लघु बजट श्रेणियों में कमी को पूरा करने से भी अधिक रही। राज्यों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के मार्ग में हमने किसी भी प्रकार के राजकोषीय कठिनाइयों को बाधक नहीं बताने दिया है।

39. अब मैं वर्ष 1992-93 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना पहली अप्रैल, 1992 से आरंभ हो रही है तथा इसका उद्देश्य दस वर्षों की अवधि में लगभग पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रत्येक क्षेत्र की निवेश संबंधी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं तथा यह महत्वपूर्ण है कि आयोजना आवंटनों से, विशेषकर आधारभूत संरचना वाले क्षेत्र की कार्यान्वयन एजेंसियां अच्छी शुरुआत करने में सक्षम हो सकें। तथापि, बृहत-आर्थिक संतुलन को फिर से कायम करने की सतत आवश्यकता के कारण हमें सीमाओं के अन्दर ही कार्य करना पड़ा, जो कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने और भुगतान-संतुलन के प्रबंध हेतु हमारे लिए अनिवार्य है। इस उद्देश्य से 1992-93 के राजकोषीय घाटे में और कमी करने की आवश्यकता है। यदि, बढ़ते हुए कर और कर-भिन्न राजस्वों के साथ-साथ सरकार के आयोजना भिन्न व्यय को सीमित रखा जा सके तो बड़े आयोजना व्यय की व्यवस्था न्यूनतम राजकोषीय घाटे के अंदर ही की जा सकती है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह एक कठिन कार्य रहा है।

40. ब्याज संबंधी प्रभार, आयोजना-भिन्न व्यय की सबसे बड़ी एकल मद है तथा 1992-93 के बजट अनुमानों में इसकी राशि 32,000 करोड़ रुपए है। यह राशि 1991-92 के संशोधित अनुमानों की तुलना में, 4,750 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाती है, जो कि आयोजना-भिन्न व्यय में 4,405 करोड़ रुपए की कुल वृद्धि से भी अधिक है। इसका अर्थ यह है कि 1992-93 में आयोजना-भिन्न व्यय की अन्य सभी मदें कुल मिलाकर भी चालू वर्ष की तुलना में वास्तविक रूप से कम हैं। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि ब्याज संबंधी प्रभार एक वचनबद्ध व्यय होता है, जो कि पिछले घाटों के संचयी

प्रभाव को दर्शाता है। इस मद को केवल उधार नी जाने वाली राशियों पर निर्भरता को कम करके ही नियंत्रित किया जा सकता है तथा मैं 1992-93 के राजकोषीय घाटे को कम करके ऐसा करने का इरादा रखता हूं। तथापि, इस कार्रवाई का लाभ केवल भविष्य में बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्रियों द्वारा ही अनुभव किया जा सकेगा। मेरे विचार से मेरे उत्तरवर्ती वित्त मंत्री चैन की नींद ले सकेंगे जबकि मेरे साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ है।

41. रक्षा सेवाओं के लिए मैं 17,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं, जो कि चालू वर्ष के 16,350 करोड़ रुपए के प्रावधान से 7 प्रतिशत अधिक है। कुछ किरायेतों और व्यय संबंधी कड़े नियंत्रण के साथ-साथ, मुझे विश्वास है कि इस आवंटन से हमारी सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने संबंधी अपनी जिम्मेदारियां को पूरा करने में समर्थ होंगी।

42. अपनी पार्टियों के चुनाव घोषणा-पत्र में हमने वचन दिया था कि हम रक्षा पेंशन भोगियों की एक रैंक एक पेंशन संबंधी लंबे समय से चली आ रही मांग के लिए कोई मुधारात्मक हल खोजेंगे। एक अधिकार-प्राप्त समिति, जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री हैं तथा भूतपूर्व सैनिक और मुख्य राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद भी इसमें शामिल हैं, इस मामले की जांच की है तथा सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, सरकार ने रक्षा कर्मियों पर लागू होने वाली पेंशन दरों में तदर्थ वृद्धि करने की स्वीकृति दे दी है। पहली जनवरी, 1992 से लागू होने वाले इस निर्णय से सशस्त्र सेनाओं के सभी रैंकों वाले छः लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचेगा, जिनमें दो लाख से भी अधिक जवान हैं और उनमें से कुछ पहली जनवरी, 1986 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। सरकार ने मृतक रिजर्व सैनिकों के परिवारों, जिन्हें परिवार पेंशन प्राप्त नहीं होती, के लिए भी परिवार पेंशन की अनुग्रह-राशि देने के आदेश जारी किए हैं। इन लाभों के परिणामस्वरूप महंगाई राहत की मौजूदा दरों के अनुसार प्रतिवर्ष 120 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होगा।

43. आर्थिक सहायता (सब्सिडी), आयोजना-भिन्न व्यय का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक होती है। पिछले वर्ष, खाद्य, उर्वरक तथा निर्यात संबंधी आर्थिक सहायताएं तीन प्रमुख आर्थिक सहायता थीं तथा इनमें तीव्रता से बढ़ोतरी, आयोजना-भिन्न व्यय में अनियंत्रित वृद्धि होने का एक मुख्य कारण है। इस वर्ष हमने निर्यात संबंधी आर्थिक सहायताओं को समाप्त करके एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। तथापि, आर्थिक सहायता संबंधी कुछ अदायगियां अभी भी की जानी हैं तथा मैं इसके लिए 480 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं।

44. खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता हमारी जनसंख्या के निर्धन और कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा संबंधी हमारी प्रणाली का एक अंग है तथा हमारी सामाजिक नीति का एक मूल तत्व है। इस प्रयोजनार्थ मैं 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं, जो कि इस प्रणाली की सामान्य

आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। 1700 पिछड़े ब्लॉकों में कार्यान्वित की जा रही नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु अतिरिक्त आर्थिक सहायता के वास्ते तथा 3 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले बहुत से गोदामों के निर्माण संबंधी लागत के लिए 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होगी। वर्ष के दौरान इन आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा करने के लिए इन मदों के लिए आवंटन में वृद्धि कर दी जाएगी।

45. इसके पश्चात् मैं उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता की ओर आता हूं, जो कि हमारी प्रणाली में सबसे बड़ी एकल आर्थिक सहायता के रूप में विकसित हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि उत्पादन के लिए उर्वरक एक अनिवार्य अंग है तथा कृषि संबंधी विकास सामान्य रूप से न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के स्तर को ऊंचा उठाने को सुनिश्चित करने के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। 1980-81 में उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता, कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और मिर्चाई तथा बाहु-नियंत्रण इन सभी के लिए केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के कुल आवंटन का 12 प्रतिशत थीं। 1991-92 में यह बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई। इस समय एक संसदीय समिति उर्वरक संबंधी मूल्य-निर्धारण और आर्थिक सहायता के समस्त मामले, जिसमें आर्थिक सहायता के पुनर्गठन संबंधी बिकला भी शामिल हैं, की जांच कर रही है। मेरा इस समिति के रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते और वर्ष के उत्तरार्द्ध में इस पर विचार करने का प्रस्ताव है। सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, मैं वर्ष 1992-93 में उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता हेतु 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं।

46. राजकोषीय घाटे की प्रबंध-योग्य सीमाओं में रखने के लिये आयोजना-भिन्न व्यय की अन्य मदों संबंधी आवंटन को सख्ती से सीमित कर दिया गया है। मैंने सभी मंत्रालयों में अपने सहयोगियों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने मंत्रालयों में व्यय नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किराया बरतने के लिये सभी संभव कदम उठाए गए हैं ताकि बजट अनुमानों में किये जाने वाले प्रावधानों में वृद्धि न हो। पिछले दो वर्षों की तरह ही, 1992-93 के बजट अनुमानों में भी अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तों के लिये, जो उस वर्ष में देय हो सकते हैं, कोई पृथक् व्यवस्था नहीं की जा रही है। सभी मंत्रालयों से इस मद पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को स्वीकृत बजट प्रावधानों के अंदर ही समायोजित करने की आशा की जाएगी।

47. इन प्रावधानों के साथ आयोजना-भिन्न व्यय के लिये कुल आवंटन की राशि 84,475 करोड़ रुपए बैठती है जो वर्ष 1991-92 के संशोधित अनुमानों की तुलना में

4,405 करोड़ रुपए अधिक है। परंतु जैसा कि मैंने पहले बताया है, केवल व्याज व्यय में ही 4,750 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि व्याज और आर्थिक सहायता की बड़ी आवश्यकताओं के कारण आयोजना-भिन्न व्यय में और कमी करना कठिन है तथा इससे आयोजना व्यय के लिये वृजतीय समर्थन भी सीमित रह जाता है। फिर भी, मैंने आयोजना-व्यय के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास किया है।

48. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता, जो कि 1991-92 के बजट अनुमानों में 14710, करोड़ रुपए थी, को 1992-93 में बढ़ाकर 16,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। कर-निर्धारण के विद्यमान स्तर पर भी करों के हिससे में 2,237 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 1,401 करोड़ रुपए की इस बढ़ोतरी में राज्यों के लिये विभिन्न योजना कार्यक्रमों के लिये आवंटनों में पर्याप्त बढ़ोतरी करना संभव हो सकेगा।

49. वर्ष 1992-93 के लिये कुल केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना परिषद 48,407 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह आयोजना हेतु 18,501 करोड़ रुपये के वृजतीय समर्थन तथा विभिन्न उपक्रमों/उद्यमों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से 29,906 करोड़ रुपए के अंशदान पर आधारित है। आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों में चालू वर्ष के स्तर की तुलना में 25 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई है तथा यह विभिन्न आधारभूत क्षेत्रों के आयोजना-परिषद में पर्याप्त वृद्धि प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, चालू वर्ष के बजट अनुमानों में रेलवे के 5,325 करोड़ रुपए के परिषद को बढ़ाकर आगामी वर्ष की आयोजना में 5,700 करोड़ रुपए; तीव्र के परिषद को 617 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,222 करोड़ रुपए; नागर विमानन के परिषद को 433 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,036 करोड़ रुपए; दूरसंचार के परिषद को 3,203 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,500 करोड़ रुपए; और उर्वरक उद्योग के परिषद को 411 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,234 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विद्युत् के लिए 6,411 करोड़ रुपए और पैट्रोलियम के लिए 6,054 करोड़ रुपए का परिषद निर्धारित किया गया है।

50. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये बजट में 2,610 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि 1991-92 के बजट अनुमानों से थोड़ा कम है, हालांकि यह संशोधित अनुमानों से अधिक है। लेकिन इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों हेतु किए जा रहे हमारे समग्र प्रयासों का एक अंश ही परिलक्षित होता है। अपने समाज के, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्गों को उस बोझ से बचाने के लिए संरक्षण देने संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारी के बारे में सरकार पूरी तरह जागरूक है,

जो कि अन्यथा, बृहन-आर्थिक स्थिरीकरण और आर्थिक पुनर्गठन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उन वर्गों पर पड़ेगा। इसलिए उन क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजनाओं के बावजूद, जहां गन वर्गों के मुकाबले अब रोजगार संबंधी आवश्यकताओं का अधिक दबाव देखने में आया है, जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं के समर्थन हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से 500 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त आवंटन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। समाज के इन सुविधाहीन वर्गों को कीमतों के दबाव से बचाने के लिए 1700 सर्वाधिक पिछड़े ब्लॉकों में मार्बजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम दरों पर खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। बजट में किए गए आयोजना संबंधी प्रावधान तथा ऊपर उल्लिखित प्रस्तावित अतिरिक्त आवंटनों को मिलाकर ग्रामीण विकास संबंधी कुल आवंटन, चालू वर्ष की तुलना में पर्याप्त वृद्धि दर्शायेगा।

51. परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये चालू वर्ष के 749 करोड़ रुपये के आयोजना संबंधी परिषद को आगामी वर्ष में बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि जनसंख्या संबंधी समस्या से निपटने के लिये सरकार के दृढ़ निश्चय की दशांता है। कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिये भी परिषद की राशि 479 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 530 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के बारे में सरकार की वचनबद्धता की पूरी तरह परिलक्षित करता है।

52. संसाधन संबंधी अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद उन अन्य क्षेत्रों के लिये, जो अपनी योजनाओं के लिये बजटीय समर्थन पर काफी सीमा तक निर्भर रहते हैं, अधिकांश को कम से कम उतनी बजटीय सहायता प्रदान की गई है, जितनी कि चालू वर्ष में दी गई थी। मैं इसमें भी अधिक राशि की व्यवस्था करता, लेकिन हमें उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं के भीतर ही रहना है। विशेष रूप से मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमें बजट में आवंटित किये जाने वाले परिषद में वृद्धि किये जाने पर ही किसी योजना संबंधी गुणवत्ता का अनुमान लगाने की प्रथा का त्याग कर देना चाहिये। हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं तथा उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग की उत्पादकता में सुधार करने के लिये अभी भी विस्तृत संभावनाएं हैं। संसाधन संबंधी विभिन्न दायों की बारीकी से जांच की जानी चाहिये तथा हम बात पर अधिक बल दिया जाना चाहिये कि उपलब्ध संसाधनों का कैसे अधिकतम लाभ उठाया जाये। समृद्धि तक पहुंचने के लिये हम अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते।

53. कर-निर्धारण की मौजूदा दरों के अनुसार आगामी वर्ष में 75,541 करोड़ रुपये की सकल कर प्राप्तियां होने का अनुमान है, जबकि इस वर्ष के संशोधित अनुमानों

में यह राशि 67,300 करोड़ रुपये है। इसमें से राज्यों का हिस्सा 18,492 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1,293 करोड़ रुपये अधिक है। आगामी वर्ष में कर-भ्रष्ट राजस्व, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2,689 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। इसमें रेलवे से 416 करोड़ रुपये का आस्थगित लाभान्श शामिल है। आगामी वर्ष के अनुमानों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभान्शों और लाभों के कारण 423 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्षों के विपरीत यह प्रस्ताव है कि हम बात को सुनिश्चित किया जाए कि ये उद्यम केवल पूंजी-निवेश के आधार पर देय लाभान्श का निर्धारण करने के स्थान पर कर-पश्चात् लाभों के एक उचित हिस्से का लाभान्श अथवा अधिशेष लाभ के रूप में प्रंतरण करें। भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने लाभों का एक बड़ा हिस्सा अंतरित करेगा।

54. पूंजीगत प्राप्ति के अन्तर्गत मैंने 5,000 करोड़ रुपये के बाजार ऋणों को जमा में लिया है। यह राशि चालू वर्ष के बजट अनुमानों की 7,500 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में काफी कम है, जो राजकोपीय घाटे को कम करने तथा उनके परिणामस्वरूप ऋण राशियों पर आश्रित न रहने संबंधी हमारे लक्ष्य को दर्शाती है। अनुदानों सहित विदेशी सहायता, किन्तु वापसी श्रदायगियों को कम करने के बाद, 5,374 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

55. चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश करने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। विकास के लिये गैर-स्कीतिकारी संसाधन जुटाने की दृष्टि से 1992-93 में इस प्रक्रिया को जारी रखने की संभावना है। तदनुसार मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में और अधिक विनिवेश करने से होने वाली 2,500 करोड़ रुपये की प्राप्ति को हिसाब में ले रहा हूं। इस राशि के अतिरिक्त, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिये 1992-93 के दौरान संसाधन प्रदान करने की दृष्टि से सरकार 1,000 करोड़ रुपये की इक्विटी की और बिक्री करने पर विचार करेगी, जिसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जिनमें महिला कामगार भी सम्मिलित हैं, तथा आर्थिक पुनर्गठन के कारण जिन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, को सहायता देने संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। इन संसाधनों का पिछड़े क्षेत्रों में, विशेष रोजगार सृजन योजनाओं के लिये विस्तृत व्यवस्था करने के लिये भी उपयोग किया जायेगा, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की है।

56. इस प्रकार, कर-निर्धारण की मौजूदा दरों के अनुसार 1,14,215 करोड़ रुपये को कुल प्राप्तियों तथा 1,19,087 करोड़ रुपये का कुल व्यय होने का अनुमान है। इनमें 4,872 करोड़ रुपये का अंतर रह जाता है।

## भाग 'ख'

57. पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर प्रणालियों में व्यापक सुधार की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया था और बताया था कि समयाभाव के कारण मुझे इस संबंध में जो मैं चाहता था वह कर पाने में कठिनाई रही। बाद में, सरकार ने डा. राजा जे. चेलैया की अध्यक्षता में एक कर सुधार समिति गठित की। समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के करों में सुधार के जटिल विषय पर हमारे कुछ अत्यंत प्रख्यात विशेषज्ञों के बहुमूल्य विचार सम्मिलित हैं और मैंने अपने बजट प्रस्ताव तैयार करने में इनके सुझावों से काफी लाभ उठाया है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का सारांश संसद में अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि समिति के विश्लेषण और उसकी सिफारिशों की युक्तिसंगतता को पूर्णतः समझा जा सके।

58. राजकोषीय विशेषज्ञों के बीच, विश्वभर से प्राप्त अनुभव के आधार पर इस बात पर सहमति है कि एक सामान्य प्रगतिशील कर प्रणाली और उसका वृद्धता से पालन करना ही ईमानदारीपूर्वक और स्वैच्छिक कर-अनुपालन को प्रोत्साहित करने का एक सर्वोत्तम तरीका है। चेलैया समिति ने इस विचार का समर्थन किया है और सिफारिश की है कि हमारी प्रत्यक्ष कर पद्धति अधिक कारगर होगी, यदि आयकर प्रणाली में आय कर की दरें कम हों और प्रारम्भिक दर तथा अधिकतम सीमांतिक दर के बीच अन्तर कम रहे तथा प्रोत्साहन छूटें कम से कम हों। मैं इस मूल्यांकन से सहमत हूँ और मेरा प्रस्ताव वैयक्तिक आयकर को निम्न प्रकार से पुनर्गठित करने का है। मेरा प्रस्ताव आय-कर छूट की सीमा, जो इस समय 22,000 रुपए है उसे बढ़ाकर 28,000 रुपए करने का है। इसमें निम्न आय वर्ग में करदाताओं को काफी राहत मिलेगी और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे, जिनमें से अनेक ने पिछले वर्ष भी ऐसे समायोजन का आग्रह किया था। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात से आश्चर्य नहीं होंगे कि मैं इस महान सदन में होने वाली कार्यवाही को ध्यानपूर्वक और सुग्राहिता से सुनता हूँ। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि केवल तीन कर दर खण्ड रखे जाएँ और प्रारम्भ में 50,000 रुपए तक कर की दर 20 प्रतिशत होगी, 1,00,000 रुपए तक मध्य खण्ड पर यह दर 30 प्रतिशत और 1,00,000 रुपए से ऊपर 40 प्रतिशत की अधिकतम दर लागू होगी। विनिर्दिष्ट हिन्दू अविभाजित परिवारों के मामले में भी तदनुकूली संशोधन किया जा रहा है। संसाधनों की गम्भीर कमी के कारण मैं एक और वर्ष के लिए 12 प्रतिशत का अधिभार बनाए रखने के लिए बाध्य हूँ। किन्तु, यह केवल उन्हीं के द्वारा देय होगा जिनकी आय एक लाख रुपए से अधिक होगी।

59. कर दरों में कटौती को देखते हुए, बहुत-सी कर छूटें, जिनसे उच्च आयकर दाताओं को बड़ी मात्रा में लाभ होता था, अब न्यायसंगत नहीं हैं। इसलिए, मेरा प्रस्ताव

आयकर अधिनियम की धारा 80ठ, 80गगक और 80गगख के अन्तर्गत कटौतियों को समाप्त करने का है। गृह सम्पत्ति से आय के परिकलन को भी इस समय अनुसृत्य कतिपय कटौतियों के संबंध में युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। तथापि, धारा 88 के अन्तर्गत उपबंध को, जिसके अंतर्गत विशिष्ट वचतों, जैसे कि जीवन बीमा, भविष्य निधियाँ इत्यादि के संबंध में कर छूट की व्यवस्था है, जारी रखा जाएगा, क्योंकि इनका लाभ निश्चित वेतन अर्जकों द्वारा उठाया जाता है। वस्तुतः मेरा प्रस्ताव, राष्ट्रीय आवास बैंक और परस्परिक निधियों द्वारा स्थापित पेंशन निधियों में अंशदानों को शामिल करके इसका क्षेत्राधिकार बढ़ाने का है। मैं यह व्यवस्था भी कर रहा हूँ कि जो उन वचत स्कीमों में अंशदान करना जारी रखना चाहते हैं, जो अब तक धारा 80 गगक और 80गगख के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र हैं, उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत कर छूट प्राप्त हो सके।

60. कहा जाता है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किन्तु हमारे कुछ करदाताओं ने बच्चों को अपने पिताओं के लिए कर आश्रय-स्थल में बदल दिया है। कर कानून में माता-पिता द्वारा दिये गये उपहारों से आय को जोड़ने का प्रावधान है किन्तु यह अन्य आय पर लागू नहीं होता, जिसमें अन्य उपाहरित परिसंपत्तियों से आय शामिल है और परस्पर उपहार देने की प्रथा का उपयोग जोड़ने से बचने के लिये किया जाता है। चेलैया समिति ने सिफारिश की है कि इस खामी को दूर करने के लिए, जिसकी वजह से काफी मात्रा में राजस्व की हानि होती है, अवयस्क बच्चों की आय को माता-पिता की आय के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस सुझाव में वजन है और मेरा प्रस्ताव इसे स्वीकार करने का है। तथापि, बच्चों में अनेक प्रतिभाओं की विद्यमानता को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से हमारे देश के बाल कलाकारों को ध्यान में रखते हुए, मेरा प्रस्ताव उनकी व्यावसायिक आय को और साथ ही अवयस्कों की किसी मजदूरी आय को इस प्रकार जोड़ने से अलग रखने का प्रस्ताव है। अवयस्क बच्चों की आय को कर प्रयोजनों के लिए माता-पिता की आय के साथ जोड़ने की प्रथा अनेक देशों में प्रचलित है।

61. आयकर दरों को पुनर्गठित करने के कारण परम्परागत रूप से 1,500 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान है। किन्तु, यह गियायती और कर छूटों में प्रस्तावित कमी करने और अवयस्क की आय के कर निरूपण में परिवर्तन से प्रतिसंतुलित हो जाएगी। यदि कर दरों को कम करने से, जैसी कि मुझे उम्मीद है, बेहतर कर वसूली होगी, तो निवल राजस्व लाभ होगा यद्यपि इसे मात्रात्मक रूप में बताना संभव नहीं है। यदि कर दाता मेरे साथ सहयोग करें तो राजस्व अर्जन में पर्याप्त वृद्धि होगी। मेरा प्रस्ताव कर-दाताओं को आय कर दरों में और कमी करके उन्हें पुरस्कृत करने का है। अब यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।

62. 80 करोड़ से अधिक की आवादी वाले हमारे देश में मुश्किल से 70 लाख लोग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर अदा करते

हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कर जाल के अंतर्गत नए करदाताओं को लाया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेरा प्रस्ताव 5 लाख रुपये से कम के वार्षिक कारोबार वाले दुकानदारों व अन्य खुदरा व्यापारियों के संबंध में एक परिकल्पित कर पद्धति लागू करने का है। विस्तृत लेखा बहियां रखने, जटिल कर विवरणी दाखिल करने और सामान्य कर निर्धारण प्रक्रिया के पालन में होने वाली कठिनाई से बचने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक मरलोकित योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत करदाता अपने कारोबार का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेगा और उस वर्ष के लिए कर के रूप में केवल 1,400 रुपये अदा करेगा। इससे संभावित करदाताओं को कर प्रणाली के अंतर्गत आने में उनकी मनोवैज्ञानिक हिचकिचाहट को दूर करने में मदद मिलेगी। यह योजना केवल ऐच्छिक आधार पर लागू की जा रही है और यह उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी आय कर-योग्य हो। छूट सीमा 28,000 रुपये तक बढ़ा देने से संभव है कि 2.5 लाख रुपये से 3.00 लाख रुपये से कम के कारोबार वाले व्यक्तियों को यह परिकल्पित कर अदा न करना पड़े।

63. दीर्घावधिक पूंजी लाभों के वर्तमान कर निरूपण की इस आधार पर आलोचना की गई है कि कर योग्य लाभ परिकल्पित करने में दी गई छूट उस अवधि से संबंधित नहीं होती जिस अवधि में परिसंपत्ति धारित की गई है। इसके अंतर्गत उस स्फीति को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है जो उस समय के दौरान हुई हो। चेलेय्या समिति ने इस समस्या के समाधान के लिए सुचकीकरण की एक पद्धति का सुझाव दिया है और मेरा प्रस्ताव उसकी सिफारिश को स्वीकार करने का है। कर योग्य पूंजी लाभों का परिकल्पन, बिक्री प्राप्तियों में से कटौती करने से पहले सामान्य स्फीति के लिए परिसंपत्ति की लागत को समायोजित करने की अनुमति देने के बाद किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के लिए समायोजित कारक को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इस प्रकार परिकल्पित दीर्घावधि पूंजीगत लाभों पर, व्यष्टियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों के मामले में 20 प्रतिशत, कंपनियों, फर्मों, व्यक्तियों की एसोसिएशनों और व्यष्टियों के निकायों के मामले में 40 प्रतिशत व अन्यो के मामले में 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। नई पद्धति से उन व्यक्तियों को लाभ होगा जिनके पूंजीगत लाभ लम्बी अवधि में प्राप्त होते हैं तथा अल्पावधि के दौरान पूंजीगत लाभ प्राप्त करने वालों को अधिक कर अदा करना होगा। ऐसा ही होना भी चाहिए। मूल्यांकन के लिए नियत तारीख को 1 अप्रैल, 1974 से बदलकर 1 अप्रैल, 1981 किया जा रहा है। इन परिवर्तनों के साथ मेरा प्रस्ताव, कर योग्य पूंजी लाभों को परिकल्पित करने में मानक कटौती को वापस लेने और साथ ही विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों में निवेशित पूंजी लाभ के लिए धारा 54B और रिहायशी मकान की बिक्री से प्राप्त पूंजीगत लाभों के संबंध में धारा 53 के अंतर्गत छूटों को वापस लेने का है।

64.1 यद्यपि मैं आयकर प्रणाली को सरल बना रहा हूं, तथापि उन कतिपय करदाताओं की श्रेणियों को प्रत्यक्षतः कुछ रियायतें दी जानी चाहिए, जो सरकार से सहानुभूति पाने की पात्र हैं।

64.2 बहुत से व्यक्तियों को विकलांग आश्रितों का प्रतिपालन करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन पर भारी बोझ पड़ता है और यह एक ऐसा बोझ है, जिसे हमें यथा-संभव कम से कम करना चाहिए। इसलिए मेरा प्रस्ताव ऐसे व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कटौती की विद्यमान राशि 6,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का है। इसके अतिरिक्त, हम कर-रियायत का लाभ सभी करदाताओं को उनकी आय को ध्यान में रखे बगैर उपलब्ध होगा।

64.3 वेतन भोगी कार्यरत महिलाएं विशेष विचार और प्रोत्साहन की पात्र हैं। इसलिए, मेरा प्रस्ताव 75,000 रुपये तक आय वाली वेतन भोगी महिलाओं के मामले में मानक कटौती की राशि 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का है। मुझे आशा है कि इससे भारतीय महिलाओं की समाजिक और आर्थिक उन्नति के प्रति मेरी वचनबद्धता के बारे में इस सदन की माननीय महिला सदस्य आश्वस्त होंगी। बदले में, मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि अपने पार्टी सम्बन्धन को ध्यान में रखे बगैर वे बजट का समर्थन करेंगी। वेतन भोगी महिलाओं के प्रति मेरी जो नरमदिली है, उससे हो सकता है मेरी पत्नी कुछ मंदेह करे। परन्तु मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पुत्रियां अपने पिता के इस अच्छे कार्य को अपना पूरा समर्थन देंगी।

64.4 बुढ़ावस्था में व्यक्तियों को प्रायः पेश आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति मेरे सम्मान के रूप में मेरा प्रस्ताव, उन व्यक्तियों के मामले में, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जिनकी सकल कुल आय 50,000 रुपये से कम है, देय निवल कर पर 10 प्रतिशत की कर छूट देने का है।

64.5 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लेखकों, नाटक-कारों, कलाकारों, संगीतज्ञों, अभिनेताओं और खिलाड़ियों की आय घटती-बढ़ती रहती है और राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के मान्यता स्वरूप उनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बचतों के संबंध में कर छूट 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी जाएगी।

64.6 भोगाल गैम दुर्घटना के प्रभावित व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर क्षतिपूर्ति दी जानी है। दुर्घटना के मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए, मेरा प्रस्ताव, सभी मामलों में ऐसे प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति को आयकर देयता से छूट देने का है।

64.7 मुझे ऐसे बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें वेतनभोगी और स्व-नियुक्त व्यक्तियों, दोनों ही के संबंध में चिकित्सा व्यय की छूट देने का क्षेत्र बढ़ाने का आग्रह किया गया है। मेरा प्रस्ताव, अस्पताल में दाखिल होने और चिकित्सा-बीमा से संबंधित प्रावधानों को काफी उदार बनाने का है। वेतनभोगी व्यक्तियों को कर लाभ अब कुछेक सरकारी मान्यताप्राप्त अस्पतालों में उपचार कराने तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसी प्रकार स्व-नियुक्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा-बीमा के संबंध में उपलब्ध कटौती की राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए की जा रही है।

64.8 इस समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अदायगियों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को आयकर से छूट उपलब्ध है। मेरा प्रस्ताव, कुछ मार्ग-निर्देशों की शर्त पर छूट का यह लाभ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देने का है।

65. इस बात की काफी अग्रसे में आलोचना होती रही है कि भागीदार फर्मों और भागीदारों, दोनों की आय पर कर लगाकर हम दोहरे कर निर्धारण को अपना रहे हैं। चेलेय्या समिति ने भी इस बात पर बल दिया है कि इस संबंध में दोहरे कर-निर्धारण से बचा जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें दोहरे कराधान से बचना चाहिए और मेरा प्रस्ताव, एक राहत उपाय के रूप में, फर्म को एक अलग कर इकाई के रूप में मानने और उसी आय पर भागीदारों के हाथ में कर लगाने की प्रथा को समाप्त करने का है। मेरा प्रस्ताव भागीदारों को फर्म की आय में से ब्याज और वेतन के लिए की गई अदायगियों के वास्ते कटौती की अनुमति देकर उसके बाद शेष आय पर फर्म के हाथों में 40 प्रतिशत की एक समान दर पर कर लगाने का है। दी जाने वाली कटौती का अनुपात फर्म के आय स्तर के साथ-साथ घटता जाता है और यह इस प्रकार निर्धारित है कि छोटी फर्मों और पेशेवर फर्मों पर कुल कर भार कम हो जाएगा। भागीदारों पर फर्मों की आय में उनके हिस्से पर कर नहीं लगेगा, यद्यपि, उन्हें वेतन और ब्याज की आय पर कर अदा करना होगा। इस पद्धति से, करदाताओं और साथ ही कर प्रशासन की दृष्टि से, प्रचुर सरलीकरण होगा, क्योंकि प्रस्तावित योजना के अंतर्गत फर्मों के पंजीकरण, भागीदारों के कर-निर्धारणों के सुधारों, जबकि फर्मों के कर-निर्धारणों को संशोधित किया जाए, आदि से संबंधित प्रक्रिया से जुड़ी जटिलताएं समाप्त हो जाएंगी।

66. पिछले वर्ष मैंने बैंकों के पास सावधि जमाओं पर ब्याज और कमीशन अदायगियों के संबंध में स्रोत पर कर कटौती से संबंधित प्रावधान लागू किए थे। किन्तु इन प्रावधानों के कार्यान्वयन के वारों में करदाताओं से काफी आलोचना हुई है। मुझे अनेक संसद सदस्यों से भी इन प्रावधानों को वापस लेने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। स्रोत पर कर-कटौती की पद्धति बहुत से देशों में कर अनुपातन लागू करने की एक मान्य पद्धति तथा उपयोगी साधन है। तथापि, एक व्यक्ति

वित्त मंत्री को संसद के माननीय सदस्यों की राय के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, चाहे वे अपनी धारणाओं से भिन्न मत रखते हों। इसलिए, मेरा प्रस्ताव इन दोनों प्रावधानों को वापस लेने का है।

67. सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 में बहुत अधिक छूटें विद्यमान हैं, जिनकी वजह से इसका प्रशासन काफी जटिल हो जाता है। कतिपय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जैसे कि शेयरों के मूल्यांकन को, भी समझाएं हैं, क्योंकि मट्टेबाजी की गतिविधियों के कारण अत्यंत ऊंची बाजार कीमतों की वजह से शेयरधारकों पर जो बोधविविधिक निवेश-कर्ता है, भारी बोझ पड़ सकता है। इस समय उत्पादक और अनुत्पादक परिसंपत्तियों के बीच भी कोई भेद नहीं है। चेलेय्या समिति ने सुझाव दिया है कि करदाताओं को उत्पादक परिसंपत्तियों में, जैसे कि शेयर, प्रतिभूतियां, बांड, बैंक जमाओं आदि निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने और साथ ही पारस्परिक निधियों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन वित्तीय परिसंपत्तियों को सम्पत्ति कर से छूट दी जानी चाहिए। व्यष्टियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों और सभी कंपनियों पर केवल अनुत्पादक परिसंपत्तियों के संबंध में, जैसे कि रिहायशी मकान जिनमें फार्म हाऊस और शहरी भूमि सम्मिलित है, जेवरों, सोना-चांदी, मोटर-कारों, वायुयानों, नौकाओं और लघु बज्रों के संबंध में डी, जिनका उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, पर सम्पत्ति कर लगाया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि 15 लाख रुपए की वृत्तिवादी छूट के साथ ऐसा कर 1 प्रतिशत की दर पर लगाया जाना चाहिए। मेरा प्रस्ताव इस भिन्नता को स्वीकार करने का है और मुझे उम्मीद है कि इस परिवर्तन से उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को प्रोत्साहित मिलेगा और अनुत्पादक आडम्बरपूर्ण सम्पदा में निवेश हताशाहित होगा।

68. पहले अपने भाषण में मैंने यह उल्लेख किया है कि सरकार पूंजी बाजार और पारस्परिक निधियों की विशेष भूमिका को, जिनमें निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियां शामिल हैं, को कितना महत्व प्रदान करती है। कर संबंधी मामलों में सभी पारस्परिक निधियों को एक समान समझने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव भारतीय प्रतिभूति एक्मचेंज बोर्ड द्वारा मान्य सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही में पारस्परिक निधियों को आयकर से छूट देने का है। मैंने भारतीय कंपनियों को, विदेश में निवेशकों को परिवर्तनीय बांड और इक्विटी जारी करने की अनुमति देने की स्कीम का भी उल्लेख किया था। मेरा प्रस्ताव इन निर्णयों से पूंजीगत लाभ और आय पर 10 प्रतिशत का रियायती दर पर कर लगाने का है, जो दर अपनदीय पारस्परिक निधियों पर लागू है। आशा है कि इन उपायों से देश में पूंजी बाजार को एक नई दिशा मिलेगी।

69. पिछले वर्ष मैंने वातानुकूलित रेस्तरांओं पर भी व्यय कर लागू किया था, ताकि अनिश्चित संसाधन जुटाए जा सकें। मुझे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस प्रावधान

का ऐसे असंख्य रेस्तराओं और छोटे स्थापनाओं पर भारी प्रभाव पड़ा है, जिनको मुख्यतः मध्यम वर्ग द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह सुझाया गया है कि रेस्तराओं में वातानुकूलन, गृहों की विपरीत, अब समूहों की खिलासिता का विषय नहीं रहा है। बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें बम्बई से प्राप्त हुई हैं। मैंने बम्बई में ठाई साल बिनाए है। इस महान शहर के नागरिकों के प्रति मेरे दिल में एक विशेष स्थान है। हाल ही के नगर निगम चुनावों में उनके मतदान के रवैये में यह बात और भी पुष्ट हो गई है। उनके प्रति मेरा एक विशेष दायित्व बन जाता है। मेरा प्रस्ताव हम शुल्क को, जहां तक रेस्तराओं का संबंध है, वापस लेने का है। यह एक प्रामाणिक बात हो जानी चाहिए कि कांग्रेस (आई) को बोट देना राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से अच्छा है। तथापि, मैंने होटल प्राप्तियों से संबंधित व्यय कर के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए हैं। मेरा प्रस्ताव होटल के कक्ष प्रभार से संबंधित देयता के लिए पात्रता की सीमा को इस समय 400 रुपए प्रति दिन से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रतिदिन करने का है। हाल ही में विदेशी भेदा दर में किए गए समायोजनों को देखते हुए, विदेशी मुद्रा में किए गए व्यय को कर से मुक्त करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, मैं इस छूट को वापस ले रहा हूं।

70. सहकारी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव सभी सहकारी समितियों को, जिनमें बैंकिंग के कारोबार में लगी शहरी सहकारी समितियां शामिल हैं, आयकर अधिनियम के क्षेत्राधिकार से छूट देने का है।

71. मैं निगमित कर प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को महसूस करता हूं। यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां कर-निर्धारण की दरों को कम करने की आवश्यकता है और मैं इसे जितनी जल्दी संभव हो कम करने की शुरुआत करने पर ध्यान देना चाहूंगा। तथापि, निगमित कर-निर्धारण पर चलेय्या समिति की विस्तृत सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं इसलिए इसकी सिफारिश प्राप्त होने तक मेरा इस क्षेत्र में प्रमुख पुनर्गठन स्थगित रखने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्तमान दर संरचना और अधिभार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बजट में मेरा प्रस्ताव दो परिवर्तन करने का है। सामान्य तथा, पूर्ववर्ती वर्षों से आगे लाया गया मूल्यह्रास और निवेश भत्ते को वर्तमान आय में से निकाल दिया जाता है। पिछले वर्ष लागू किए गए मूल्यह्रास भत्ते के युक्तिकरण के अनुरूप मेरा प्रस्ताव कर निर्धारण वर्ष 1992-93 के संबंध में उन कंपनियों के मामले में जहां ऐसी राशि 1,00,000 रुपए से अधिक है, आगे ले जाने वाले मूल्यह्रास और निवेश भत्ते के लिए मुजरई की मात्रा को ऐसी राशि की दो-तिहाई तक सीमित रखने का है और शेष एक-तिहाई राशि के समायोजन की अनुमति निर्धारण वर्ष 1993-94 में होगी। इसके अतिरिक्त, इस व्यापक आलोचना को ध्यान में रखते हुए, कि कुछ व्यापारिक खर्चों के संबंध में सीमाएं कृत्रिम हैं, मैं चलेय्या समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ मर्दों को उद्धार बना रहा हूं।

72. कर कानूनों में जटिलताओं के संबंध में मुझे ऐसे कुछ अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि जब कभी भी अभीष्ट लेनदेनों के संबंध में करदेयता के बारे में किसी करदाता को कोई संदेह हो तो सरकार को अग्रिम निर्णय देना चाहिए। यह प्रथा बहुत से देशों में प्रचलित है। ऐसे सुझाव को कार्यान्वित करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं फिर भी अनावश्यक मुकदमेबाजी में बचने और बेहतर करदाता संबंध प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारतीय मूल के अतिवासियों से संबंधित कारोबार के बारे में अग्रिम निर्णय देने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है और इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। बाद में, प्राप्त होने वाले अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। सरकार एक राष्ट्रीय प्रत्यक्ष-कर न्यायालय स्थापित करने की भी योजना तैयार कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्यक्ष कर मामलों में मुकदमों का शीघ्र निपटान हो सके। इसके साथ-साथ सरकार, प्रत्यक्ष-कर संहिता के संबंध में यथा-शीघ्र एक विधेयक भी पेश करना चाहेंगे जिसमें सभी तीनों प्रत्यक्ष करों को समेकित किया जाएगा, जिससे कि कानून को असानी से समझा जा सके और कर प्रशासन सरल बन सके।

73. प्रत्यक्ष-कर कानूनों में अन्य छोटे परिवर्तनों के संबंध में मेरा प्रस्ताव सदन का और अधिक समय लेने का नहीं है।

74. प्रत्यक्ष-कर संबंधी मेरे प्रस्तावों से 795 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है। इस राशि में से 435 करोड़ रुपए राज्यों को प्राप्त होंगे।

75. मैं अब अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों की ओर आता हूं।

76. हमारे उद्योग और व्यापार नीति के विशेषज्ञों की संघे अरसे से यह शिकायत रही है कि हमारी सीमा शुल्क की दरें काफी अधिक और हमारे प्रतियोगी देशों की प्रवृत्तियों से काफी हटकर हैं, जिन सभी ने टैरिफों को बहुत साधारण स्तर तक कम कर दिया है। मेरे सहयोगी, माननीय वाणिज्य मंत्री ने मुझसे बार-बार कहा है कि हम विश्व बाजारों में इन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आशा नहीं कर सकते अगर हम उच्च टैरिफ दरों को बनाए रखें, जिनका प्रभाव उच्च लागत वाले औद्योगिक ढांचे के मूल्य में होता है। यह उन्हीं मागनिर्देशों के अनुसार है, जैसा कि पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था। चलेय्या समिति, जिसे सीमाशुल्कों के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए कहा गया था, ने टैरिफ के सामान्य स्तर में कभी करने, टैरिफ दरों के विस्तारण में कटौती करने और कई अन्य-प्रयोग छूट और रियायतें समाप्त करके प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है। समिति ने यह भी मही सुझाव दिया है कि सुधार की प्रक्रिया धीरे-धीरे होनी चाहिए ताकि राजस्व को संभावित हानि और उस गति जिस पर घरेलू उद्योग को

प्रतिस्पर्धा करनी होगी, दोनों रूप में समायोजन के प्रभाव को संयत किया जा सके। मैं सीमा-शुल्क ढाँचे में सुधार करके इस बजट से एक पर्याप्त गृहभान करने हुए इन मिकारिशों पर अमल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

77. पिछले वर्ष मैंने सीमा-शुल्क का मूल्यानुसार मूल और आनुपंगिक दरों को अधिकतम 150 प्रतिशत तक करके आयात शुल्कों में कमी करने का प्रक्रिया शुरू की थी। मैं अब आयात शुल्कों का मूल और आनुपंगिक दरों (विशिष्ट दरों सहित) को अधिकतम 110 प्रतिशत तक कम करके शीर्ष टैरिफ स्तर को और कम करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें यात्रो-भाज-सामान और मध्यमार्गिक पेय पदार्थ इसके अपवाद होंगे। इस प्रस्ताव से 1700 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

78. मेरा अगला प्रस्ताव पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क से संबंधित है। परियोजना आयातों सहित पूंजीगत वस्तुओं पर सामान्य शुल्क वर्तमान में 80 प्रतिशत है जो 110 प्रतिशत की शीर्ष दर से कम है। तथापि, पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क घटाने की प्राथमिकता देने का अच्छा मामला है क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं पर उच्च शुल्क से इकाई की पूरी अवधि के दौरान उत्पादन लागत में स्थायी वृद्धि की जाती है। निर्यातोन्मुख उद्योगों में नए निवेश को प्रोत्साहित देने के लिए हमें तांत्रिक गति से पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क दर में कमी करनी चाहिए। इसलिए मैं परियोजना आयातों और सामान्य मशीनों पर शुल्क दर को 80 प्रतिशत से कम करके 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए परियोजना आयातों सहित पूंजीगत वस्तुओं के मामले में, मैं आयात शुल्क को 60 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। कोयला खनन और कच्चे पेट्रोलियम परिशोधन की परियोजनाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में, मैं 30 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने हुए आयात शुल्क में और भी अधिक कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, 30 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत की वर्तमान रियायती शुल्क दर को 30 प्रतिशत की एक समान दर पर युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। मैं अन्य पूंजीगत वस्तुओं, जिन पर वर्तमान में 80 प्रतिशत से अधिक शुल्क लगता है, पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। विशिष्ट मशीनों के घटकों की शुल्क दरों में उपलब्ध विद्यमान रियायत, जिससे वे इन मशीनों की मशीनों पर लागू दरों से कम दरों पर आयात कर सकते हैं, को जारी रखने का प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों से भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर विशेषतः पिछले वर्ष लागू किए गए विभिन्न दर समायोजन को ध्यान में रखते हुए, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप लगभग 840 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

79. टैरिफ शीर्ष दर में कटौती को देखते हुए, मैं इस अवसर पर रियायती शुल्क आयातों के लिए कुछ अन्य

प्रयोग अधिसूचनाओं को भी समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। युक्तिसंगत बनाने की इस प्रक्रिया में कुछ शुल्कों में सीमांतिक वृद्धि हो सकती है। तथापि, शुल्क दरों में समग्र कटौती को देखते हुए, उद्योग को ऐसा सीमांतिक वृद्धियों का वर्दाश करने योग्य होना चाहिए।

80. पिछले बजट में मैंने सीमा-शुल्क की आनुपंगिक दरों को युक्तिसंगत बनाने का कुछ प्रस्ताव रखा था। मैं शुल्क खण्डों की संख्या चार तक कम करके आनुपंगिक शुल्क ढाँचे को और युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस सब में 125 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान है।

81. कृषि एक ऐसा मूल आधार है, जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर करता है और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निविष्टियों पर हमेशा प्राथमिकतापूर्ण कर प्रणाली लागू की गई है। इस मिश्रित के अनुरूप, मैं 15 निर्दिष्ट कोटनाशकों पर शुल्क दर को, विद्यमान 110 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक, उन्हें इस छूट के लिए पात्र कोटनाशकों की सूची में शामिल करते हुए, कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं दो कोटनाशक मध्यवर्तियों पर आयात शुल्क को विद्यमान 120 प्रतिशत के स्तर से कम करके 65 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार मैं तीन निनिर्दिष्ट कोटनाशक मध्यवर्तियों की उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इन प्रस्तावों से लगभग 8 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

82. सफल कृषि विकास के लिए नए बीजों, जो उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, का प्रयोग करने की आवश्यकता है तथा आयातित बीज और पौध-रोपण सामग्रियाँ इस प्रक्रिया में सहायक बन सकती हैं। इसलिए, मैं तेलहनों, सब्जियों, फलों और सजावटी पौधों के बीजों, फलों के कन्दों और बल्बों; बुझाई और पौध रोपण के प्रयोजनार्थ फूल के पौधों की कलम अथवा पौध, फलों के पौधों और दालों के बीज को आयात शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। सक्षम पौध-रोपण सुनिश्चित करने के लिए, मैं चावल प्रतिरोपकों पर से आयात शुल्क 80 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

83. पेट्रो-रसायन उद्योग के कुछ मूल संभरक भण्डार जो उद्योग का आधार हैं, उच्च शुल्क दरों से प्रभावित हैं। इस क्षेत्र में शुल्क में कटौती करने और उन्हें युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं प्रापिलीन पर आयात-शुल्क 120 प्रतिशत से कम करके 85 प्रतिशत, बूटाडीन पर 55 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत, और बेन्जीन पर 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं ईथाइल बेन्जीन और स्टीरीन पर, जो पॉलीस्टीरीन के विनिर्माण की अनिवार्य निविष्टियाँ हैं, 40 प्रतिशत के एक समान आयात-शुल्क का भी प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, मैं कुछ निर्दिष्ट संभरक

भंडारों पर, जिनका प्रयोग पॉलीथीलीन के विनिर्माण में होता है, आयात शुल्क 120 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता है। इन प्रस्तावों से लगभग 26 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

84. एस्वेस्टम सीमेंट उद्योग, जो आबाम, जलपूर्ति और मिर्चाई क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, को राहत देने के उपाय के रूप में, मैं एस्वेस्टम फाटवर पर आयात-शुल्क घटाकर 90 प्रतिशत से 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 18 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

85. फिल्मों, हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है। इसलिए, मुझे इस महत्वपूर्ण उद्योग की आर्थिक स्थिति के बारे में चिंता है। फिल्म उद्योग, जिसे केवल टी.वी. और थियेट्रो में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मैं सिनेमाटोग्राफ फिल्म के आयातित रंगीन नेगेटिवों पर आयात शुल्क को विद्यमान स्तर से 20 प्रतिशतों तक कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 8 करोड़ की राजस्व-हानि होगी।

86. मैं, प्लाडिंग और फॉल्कोजिप्स ईटों तथा टमार्टी संघटकों के विनिर्माण के लिए आवश्यक मशीनों की विनिर्दिष्ट मशीनों पर आयात-शुल्क कम करने का प्रस्ताव करता हूँ।

87. पिछले वर्ष समाचार पत्र उद्योग को राहत के रूप में मैंने मानक अखबारी कागज को सीमा-शुल्क से पूरी छूट दे दी थी। मैं महसूस करता हूँ कि प्रेम में मेरे समर्थन से कुछ और मजबूती आएगी। मैं अब चिकने (ग्लेज्ड) अखबारी कागज, जिस पर इस समय 550 रुपए प्रति मी. टन की दर लागू है, शुल्क अदायगी से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से लगभग 3 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

88. मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ कि भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित भारतीय द्वारा अपने माज-सामान के भाग के रूप में सोने के आयात की अब अनुमति होगी। प्रत्येक यात्री को अब 5 किलोग्राम तक सोना लाने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे सोने पर आयात-शुल्क प्रति 10 ग्राम 450 रुपए होगा, जो मूल्यानुसार रूप में लगभग 15 प्रतिशत बँटता है। यह शुल्क पारिवर्तीय विदेशी मुद्रा में देय होगा। मुझे विश्वास है कि इस धातु के देश में अब तक तस्करी के लाभप्रद व्यापार में संलग्न व्यक्तियों को छोड़कर, इस कदम का सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा।

89. इस बजट में सीमा-शुल्क को पुनर्गठित करने के लिए किया जा रहा प्रयास ऐसी प्रक्रिया की एक शुरुआत है, जिससे तीन से लेकर चार वर्षों की अवधि में हमारे सीमा शुल्कों में अन्य विकासशील देशों के तुलनीय स्तर तक क्रमिक रूप में कमी हो जाएगी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता चाहूँगा कि उन्हें इस बात से भय करने की आवश्यकता

नहीं है कि शुल्कों में कमी करने से भारत का विजौद्योगिकीकरण हो जाएगा। इसके विपरीत, यह कटौती भारतीय उद्योग को एक ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जिसमें वह विषय अर्थ-व्यवस्था के साथ और अधिक एकीकरण तथा प्रौद्योगिकी अपनकर अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकता है। अगर हमें वास्तव में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो यह अनिवार्य है। हम भारतीय उद्योग की प्रतियोगी क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहन संबंधी प्रभावी उपाय करेंगे। सीमा-शुल्क में अन्य परिवर्तनों के साथ सीमा-शुल्क के प्रस्तावित वित्त पुनर्गठन से 20, 23.35 करोड़ रुपए की निवल हानि होगी। यह हानि परम्परागत तरीके से अनुमानित है और यह संभव है कि इसके अधिमूल्यांकन की संभावना हो सकती है अगर हम अधिक मात्रा में आयात की अनुमति देकर भुगतान संतुलन में पर्याप्त सुधार की अनुमति दें और इस प्रकार सीमा-शुल्क राजस्व का उच्चतर स्तर प्राप्त करें।

90. उत्पाद-शुल्कों के क्षेत्र में, मैं जहाँ भी आवश्यक हो राहत प्रदान करने हुए और निस्संदेह सीमा-शुल्कों को पुनर्गठित करने से होने वाली राजस्व हानि को प्रतिशुलित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाकर उत्पाद शुल्क ढाँचे को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य द्वारा मार्ग निर्देशित हुआ हूँ।

91. वर्ष 1991-92 का बजट प्रस्तुत करने समय, मैंने अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को सरल और युक्तिसंगत बनाने के अपने आशय का उल्लेख किया था ताकि इस प्रणाली में होने वाले विलम्बों को दूर किया जा सके और कर संग्रहकर्ता तथा करदाता के बीच परस्पर क्रिया को न्यूनतम किया जा सके। मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 के अंतर्गत लाइसेंसिंग नियंत्रणों, उत्पादन और विनिर्माण को समाप्त करके इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रस्ताव करता हूँ। निर्धारितियों को केन्द्रीय शुल्क प्राधिकारियों के पास केवल अपना पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, निर्धारितियों को प्रत्येक पांच वर्ष पर अपने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंसों का नवीकरण कराना होता है। पंजीकरण तब तक वैध रहेगा जब तक निर्धारित विनिर्माण क्रियाकलाप जारी रखता है। मैं इस प्रयोजन के लिए कानून में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

92. माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन सन् 1976 में एक समझौता आयोग स्थापित किया गया था। उसी आधार पर, विभाग और निर्धारितियों के बीच सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी विवादों से निपटने के लिए मैं एक समझौता आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह कर संबंधी विवादों को शीघ्रता से निपटाने में सहायक होगा।

93. माननीय सदस्यों को यह भी स्मरण होगा कि सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों के निर्धारण और संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अनुसरण में मूल्यांकन

में संबंधित विवादों के अधिनिर्णयन के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने के लिए 1986 में एक कानून बनाया गया था। अपरिहार्य कारणों से, इस न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं हो सकी। मैं सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क राजस्व अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1986 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए विधान पेश करने और न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

94. आवासीय क्षेत्र सामाजिक रूप से और राजश्व के अक्सर पैदा करने, दोनों ही दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं और इसलिए, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं 25 प्रतिशत लाल मिट्टी, जो अल्युमीनियम उद्योग का एक अपशिष्ट उत्पाद है, बाली ईंटों और टाइलों का न्यूनतम उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं हल्के वजन वाले कंक्रीट इमारती प्लाकों को भी उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अनिश्चित मैं पृथ्वी संरचित इमारतों पर उत्पाद शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं प्लास्टिक, लोहे और इस्पात में बने दरवाजों और खिड़कियों को पूरी तरह छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूँ। जिनमें प्रसंगवश हमारी नष्ट होती हुई वन संपदा को संरक्षण प्राप्त होगा। इसके अनिश्चित मैं पैनल दरवाजों, जिनपर वर्तमान में 30 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है, को पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव में लगभग 4 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

95. ग्लाम कन्टेनर उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। मैं ग्लाम कन्टेनरों पर उत्पाद शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। अर्द्ध स्व-चालित प्रक्रिया और माउथ ब्लोन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित ग्लाम कन्टेनरों पर भी उत्पाद शुल्क विद्यमान 30 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के स्तर से घटाकर क्रमशः 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इन प्रस्तावों से 30 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

96. वर्तमान में वस्त्रोद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के बीच शुल्क दरों में व्यापक भिन्नता है। मेरा प्रार्थमिक उद्देश्य टैरिफ टैबल को सरलीकृत करना और युक्तिसंगत बनाया तथा विभिन्न वस्त्र रेशों और यार्न के बीच शुल्क संबंधी भिन्नताओं को कम करना है।

97. मैं सूती धागे, सेल्यूलोस स्पन यार्न और पॉलिएस्टर मिश्रित यार्न पर उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाने और उसे पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं सूती धागे पर दरों की बहुलता को कम करके उसे केवल पांच शुल्क खंडों में अपनाने का प्रस्ताव करता हूँ। सेल्यूलोसिक स्पन यार्न पर उत्पाद शुल्क को भी इस प्रकार तीन खंड बनाकर युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

98. मैं विस्कोस रेशे पर मूल उत्पाद शुल्क को 10.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम, विस्कोस फिलामेंट 561 G/92-13

यार्न पर 12 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम और एक्त्रीलिक फाइबर पर 9.24 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। पॉलिएस्टर मिश्रित यार्न पर शुल्क दरों को भी युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

99. मोटे (गोडी) ऊन के उद्योग के लिए विशिष्ट और मिश्रित अपशिष्ट दोनों कच्ची सामग्रियाँ हैं। मैं दोनों पर आयात शुल्क को बराबर करके 110 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

100. अनिश्चित उत्पाद शुल्क, जिसकी प्राप्ति, राज्यों को जाती है, से राजस्व जुटाने की दृष्टि से मैं शुल्क खंडों को पुनर्गठित करके संसाधित सूती फैब्रिकों पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

101. नायलोन और पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न उद्योग में बहुत सी इकाइयाँ कठिनाई के दौर से गुजर रही हैं। राहत के एक उपाय के रूप में, मैं नायलोन फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 63 रुपये से घटाकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम तथा केप्रोलेक्टस पर आयात शुल्क को भी 80 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क को भी 70 रुपये से घटाकर 62 रुपये प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूँ।

102. हथकरघा क्षेत्र द्वारा पटसन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, मैं लच्छे वाले पटसन यार्न को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, पंजीकृत सहकारी समितियों, महिला सरकारी समितियों आदि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्मित किए जाने वाले पटसन उत्पादों को भी उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से मुक्त करने का प्रस्ताव है।

103. रेशम उद्योग को राहत देने के एक उपाय के रूप में, मैं कच्चे रेशम पर आते शुल्क को 55 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

104. वस्त्र उद्योग में संबंधित प्रस्तावों के पैकेज में लगभग 25 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

105. अब मैं युक्तिकरण और अनिश्चित राजस्व जुटाने में संबंधित प्रस्तावों का जिक्र करूँगा।

106. इस समय, उत्पाद शुल्क कुछ वस्तुओं पर मूल्यानुसार तथा अन्य कई वस्तुओं पर विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। पिछले कई वर्षों में, प्रशासनिक कारणों से, मूल्यानुसार शुल्कों को धीरे-धीरे विनिर्दिष्ट दरों अथवा मूल्यानुसार एवं विनिर्दिष्ट दरों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। विनिर्दिष्ट दरों की तुलना में मूल्यानुसार दरों को तरजीह दी जानी चाहिए क्योंकि मूल्यों में वृद्धि होने के कारण इनसे राजस्व में बढ़ोतरी सुनिश्चित होती है तथा चेलैया समिति ने बहुत सी वस्तुओं के संबंध में मूल्यानुसार

दरों को अपनाने की सिफारिश की है। इसने यह भी सिफारिश की है कि जिन मामलों में निर्दिष्ट दरों को लागू रखा जाना है, सूत्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए उन दरों को प्रत्येक वर्ष संशोधित किया जाना चाहिए। जहाँ भी संभव है, उन वस्तुओं के संबंध में मूल्यानुसार शुल्क प्रणाली को अपनाकर मैं साधारण सी शुल्कान्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

107. मुख्य अलौह धातुओं अर्थात् ताम्बा, सीसा, जस्ता तथा उनके उत्पादों के संबंध में मैं मौजूदा विनिर्दिष्ट शुल्क दरों के स्थान पर 10 प्रतिशत की एक समान मूल्यानुसार शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। जहाँ तक लोहे और इस्पात का संबंध है, इनके प्राथमिक और अर्ध-परिशुद्ध स्वरूपों पर सामान्यतः विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगता है। कुछ प्रणामनिक कारणों से मैं मिश्रितों तथा मत्तानों, छद्म आदि जैसे कल्पित बेल्डित उत्पादों, जो स्टेनलम स्टील से तैयार नहीं होते, जैसी शर्तों पर उत्पाद शुल्क की विनिर्दिष्ट दरों को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। इन उत्पादों के संबंध में, मैं विद्यमान दरों, जो वर्तमान में 300 रुपये से लेकर 1,800 रुपये प्रति मीट्रिक टन के बीच है, को बढ़ाकर 400 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन के बीच करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, मैं लोहे की गठी वस्तुओं और अन्य इस्पात उत्पादों के संबंध में 10 प्रतिशत का एक समान उत्पाद शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन प्रस्तावों से लगभग 400 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा।

108. पिछले वर्ष मैंने, अपने बजट भाषण में कहा था कि प्रत्येक वित्त मंत्री को धूम्रपान, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर रोक लगाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी यह हानि अभी भी जारी है तथा यदि इस उपयोगी काम के लिए राजकोषीय का प्रयोग करने का मैं एक और प्रयास न करूँ तो अपने कर्तव्य पालन में यह मेरी असफलता रहेगी। यद्यपि 60 मिलीमीटर से कम आकार की बिना फिल्टर वाली सिगरेटों पर शुल्क में वृद्धि करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन अन्य सभी सिगरेटों पर उनके आकार के आधार पर शुल्क दरें 30 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति हजार तक बढ़ाई जा रही हैं। इन प्रस्तावों से 325 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

109. मैं, पोलिस्टीन, कम घनत्व वाली पोलिथिलीन, उच्च घनत्व वाला पोलिथिलीन तथा पोलिप्रोपिलीन जैसी कठिना प्लास्टिक रेसिनों पर उत्पाद शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 165 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा।

110. घड़ियों पर 5 प्रतिशत की बहुत कम दर से शुल्क लगाया जाता है जो कि सामान्य शुल्क प्रणाली से हट कर है। मैं इस दर को बढ़ा कर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 12 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

111. मैं सीमेंट पर उत्पाद शुल्क को 215 रुपये से बढ़ाकर 290 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ। लघु सीमेंट संयंत्रों में तैयार किए गए सीमेंट पर भी उत्पाद शुल्क को 90 रुपये से बढ़ाकर 165 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया जाएगा और इस प्रकार लघु सीमेंट संयंत्रों के पक्ष में 125 रुपये प्रति मीट्रिक टन के मौजूदा शुल्क अंतर को बनाए रखा गया है। तथापि, मैं सफेद सीमेंट पर शुल्क को 40 प्रतिशत से घटा कर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि इसके भार को साधारण सीमेंट के बराबर हो रखा जा सके। इन प्रस्तावों से 376 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होने का अनुमान है।

112. मैं रंगरोशन पर उत्पाद शुल्क को दरों को 15 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर क्रमशः 20 प्रतिशत और 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 35 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्ति होगी।

113. मैं आर्गेनिक सरफेस सक्रिय कारकों पर उत्पाद शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

114. इस समय मोटर साइकिल और स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों पर इंजन क्षमता के अनुसार, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगता है। मैं 75 सी.सी. तक की इंजन क्षमता वाले सभी दोपहियों पर 15 प्रतिशत का दर से तथा 75 सी.सी. से अधिक इंजन क्षमता वाले अन्य दोपहियों पर 25 प्रतिशत का दर से एक समान शुल्क लगाकर शुल्क संरचना को युक्तिपूर्ण बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इन प्रस्तावों से 80 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्ति होगा।

115. मैं कोको तथा कोको से बना वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 24 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्ति होगा।

116. मैं तारों और केबलों पर उत्पाद शुल्क में वर्तमान स्तर से पांच प्रतिशतों की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 60 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है।

117. मैं टायरों, ट्यूबों तथा गलियों के उत्पाद शुल्क की मौजूदा विनिर्दिष्ट दरों में बढातरी करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, मैं मोपेड टायरों पर शुल्क को 30 रुपये से घटाकर 25 रुपये प्रति टायर करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 40 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा।

118. इस समय, मूल उत्पाद शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है, कुछ आवश्यक मद, जैसे चाय, काफी, चीनी, माचिस, विरोसीन तथा

वनास्पति को इसमें पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त, हाई स्पीड डीजल तेल तथा दोपहियों पर 5 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मैं, उन उत्पादों पर जिन पर इस समय शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, यह वृद्धि पैट्रोविषम उत्पादों पर लागू नहीं होगी। मैं लम्बे समय तक प्रयोग में आने वाली कुछ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कि मोटर-कारों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं, जैसे टेलीविजन सेटों को इस अतिरिक्त शुल्क से मुक्त करने का भी प्रस्ताव करता हूँ क्योंकि ये उद्योग एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इन प्रस्तावों से 1,025 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

119. पिछले वर्ष व्यापार नीति में लागू किए गए परिवर्तनों से विनिर्माण के उच्च स्तरों पर निर्यात के लिए विशेषतः प्रोत्साहन समाप्त हो गए हैं। यद्यपि प्रोत्साहन की किसी एक समान पद्धति को सामान्यतः प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन कुछ प्राथमिक उत्पादों के निर्यात के संबंध में कुछ हतोत्साहन का मामला भी बनता है क्योंकि इन उत्पादों का मुख्यवर्धित रूप में निर्यात किया जा सकता है। मैं परिष्कृत चमड़े को कुछ किस्मों तथा पालिश न किए गए ग्रेनाइट के निर्यात पर 10 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे कि निर्यातक चमड़ा उत्पादों तथा पालिश किए गए ग्रेनाइट की तरफ आकर्षित हों। मैं लीड-अपस्क पर भी 5 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगा रहा हूँ। इन प्रस्तावों से 142 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है।

120. उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क टैरिफ में परिवर्तन करने के लिए मैंने वित्त विधेयक में कई संशोधनों का प्रस्ताव किया है। ये संशोधन सामान्यतः समर्थनकारी उपबंध हैं तथा राजस्व का दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त, कुछ संयुक्त अधिसूचनाओं में संशोधनों करने का भी प्रस्ताव है। सदन का समय बचाने के दृष्टि से मेरा उनके संबंध में उल्लेख करने का प्रस्ताव नहीं है।

121. उत्पाद शुल्क में उपरिलिखित परिवर्तनों संबंधी प्रस्तावों से 2,515.70 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। घोषित की गई रियायतों और राहतों संबंधी कुल राशि 304.80 करोड़ रुपए बैठती है। उत्पाद शुल्क से 2,210.90 करोड़ रुपए के प्राप्त विभाजन योग्य निवल अतिरिक्त राजस्व में से केन्द्र का हिस्सा 1,146.53 करोड़ रुपए तथा राज्यों का हिस्सा 1,064.37 करोड़ रुपए होगा।

122. सीमाशुल्कों और उत्पाद शुल्कों, दोनों को मिलाकर मेरे प्रस्तावों के फलस्वरूप निवल प्राप्ति के रूप में अप्रत्यक्ष करों से केवल 187.55 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाई जा सकेगी। चूंकि सीमाशुल्कों में हानि होने

पर यह पूर्णतः केन्द्र को ही उठानी पड़ती है जब कि उत्पाद शुल्क संबंधी राजस्व लाभ को राज्यों के पास पड़ा जाता है, इस प्रकार केन्द्र के राजस्व में 886.82 करोड़ रुपए की हानि होगी जबकि राज्यों को 1,064.37 करोड़ रुपए तक का लाभ होगा।

123. पहली मार्च, 1992 से प्रभावी होने वाली सीमा-शुल्कों और उत्पाद शुल्कों की दरों में परिश्रमों से संबंधित अधिसूचनाओं की प्रतियां यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

124. मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में संशोधन जो प्रस्ताव किए हैं, उन दोनों प्रकार के करों की हिसाब में लेने के बाद केन्द्र को 517 करोड़ रुपए की निवल राजस्व हानि होने का अनुमान है जबकि राज्यों को 1,560 करोड़ रुपए का लाभ होगा। परिणामस्वरूप, 1992-93 में केन्द्र का वर्ष का बजटीय घाटा 5,389 करोड़ रुपए तथा उस वर्ष का राजकोषीय घाटा 34,108 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

125. हमारा राष्ट्र सदा जवाहरलाल नेहरू का उनकी इस दूरदर्शिता और दृढ़ आग्रह के लिए कृतज्ञ रहेगा कि भारत का सामाजिक और आर्थिक रूपान्तरण एक जुड़े समाज के ढांचे में करना होगा जो संसदीय प्रजातंत्र और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध हो। विकासशील विश्व के भविष्य के लिए भारत का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी विकास संभावना को समझने के लिए हमें सृजनात्मकता, आदर्शवाद, साहस और ऐसे उद्यम की मानवीय भावना का एकक्षोरना है, जो हमारे लोगों में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। एक द्वितीय औद्योगिक क्रांति तथा एक दूसरी कृषि क्रांति के लिए हमें अपने सभी अस्तित्वित संसाधनों का दोहन करना है। हमारी अर्थ व्यवस्था, राजतंत्र और समाज को असाधारण रूप से लचीला और जागरूक बनना होगा, यदि हमें अवसरों का पूरा लाभ उठाना है और आर्थिक प्रक्रियाओं के बढ़ते हुए विष्वव्यापीकरण से जुड़े जोखिमों को कम से कम करना है। यदि हमें विकासशील विश्व अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते हुए सीमांतिकरण से बचना है तो हमें सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा। पिछले आठ महीनों में हमारी सरकार द्वारा किए गए आर्थिक नीति संबंधी परिवर्तन इसी दूरदर्शिता द्वारा प्रेरित हैं। हमारी पार्टी को राष्ट्रीय सेवा की एक महान परम्परा विरासत में मिली है। इस परम्परा के ही अनुरूप हम सुधार प्रक्रिया के प्रति एक दृढ़ और उद्देश्यपूर्ण दिशा-निर्देश की भावना प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं, ताकि भारत को यह प्राचीन भूमि अंतर्राष्ट्रीय विरादरी में अपना सही और गौरवपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त कर सके। यह बजट, इस महान राष्ट्रीय ध्येय की सफलतापूर्वक प्राप्ति, भारत को युद्ध, जरूरत और शोषण के भय से मुक्त बनाने के लिए, भारत के प्रति एक ऐसे अंशदान का द्योतक है जो हमारे गणतंत्र के संस्थापकों के सपनों के लायक हो। हम हर कीमत अदा करेंगे, प्रत्येक

नोक्ष बर्दाश्त करेंगे और इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए कोई भी बलिदान देंगे। भारत पुनः प्रगति के रास्ते पर है। हम भविष्य की प्रतीक्षा करेंगे।

126. महादेव, मैं यह बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीमती जानकी कवसाजिया, ग्रामर सचिव (बजट)

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 1992

F. No. 1571-BCD/91 :—Budget (1992-93)  
Speech of Shri Manmohan Singh, Minister of Finance :—

### PART A

Sir,

I rise to present the budget for 1992-93.

2. The fiscal year now drawing to a close has been a difficult one by any standards. It has been a year of crisis and of crisis management. It has also been a year of great economic challenges and bold new initiatives.

3. Honourable Members would recall that when the new Government assumed office eight months ago, we inherited an economy on the verge of collapse. Inflation was accelerating rapidly. The balance of payments was in serious trouble. The foreign exchange reserves were barely enough for two weeks of imports. Foreign commercial banks had stopped lending to India. Non-Resident Indians were withdrawing their deposits. Shortages of foreign exchange had forced a massive import squeeze, which had halted the rapid industrial growth of earlier years and had produced negative growth rates from May 1991 onwards.

4. This is the grim legacy we inherited.

5. Our first and immediate challenge was to arrest the slide and restore India's credibility both domestically and in the eyes of the world. To achieve this objective we had to take immediate measures to avert a default in international payments and also take steps to restore macro-economic balance in the economy in the short run, with a view to controlling inflation and reducing the balance of payments deficit to a manageable level. Our medium term objective was to place the economy back on the path of high and sustainable growth.

6. The new Government took several initiatives in pursuit of these objectives. We took emergency measures to prevent a default in external payments,

which would have been highly disruptive. The previous Government had already decided to use a part of the gold held by the Reserve Bank of India to mobilise temporary liquidity abroad. We did not consider it prudent to reverse this decision. But we promised to redeem the gold at the earliest opportunity and we have kept our word. We began the process of restoring macro-economic balance by seeking to reduce the fiscal deficit which had grown very large in the previous year. We also embarked on a medium term programme of structural reform, including new initiatives in trade policy and industrial policy aimed at improving the efficiency, productivity and international competitiveness of Indian industry. Our longer term objective is to evolve a pattern of production which is labour intensive and generates larger employment opportunities in productive higher income jobs, and reduces the disparities in income and wealth between rural and urban areas.

7. Production was bound to suffer in a year of crisis and this has happened in 1991-92. Agricultural production was below target in the kharif season, but prospects for the rabi crop look good. Industrial production suffered because of severe import compression and tight credit conditions. However, the infrastructure sectors, which are the foundation on which future industrial growth depends, have done well. Overall, I expect GDP growth in 1991-92 to be around 2.5%. I expect a distinct improvement in 1992-93, and a return to high growth in 1993-94. However, this revival can be achieved only if we persevere unflinchingly with the process of stabilisation and economic reform begun in the current year.

8. Stabilisation and structural adjustment are never painless or quick, especially when we are dealing with imbalances and structural rigidities which have built up over several years. It will take sustained effort, over at least three years, to bring the economy back to a path of rapid and sustainable growth. A firm commitment to austerity, the pursuit of excellence and the promotion of efficiency and productivity for the benefit of the common people has to be an integral part of this effort. Given our limited resources, our people cannot afford to copy the soulless consumerism and the wasteful life styles of the affluent countries of the West. Conspicuous consumption has to be actively discouraged. The virtues of thrift have to be emphasised. The owners of wealth, as Gandhiji used to say, must learn to regard themselves as trustees of Society. We cannot postpone structural reform and adjustment, but we must ensure that the burden of adjustment on the poorer and weaker sections of our society is ameliorated to the maximum possible extent. We are travelling through difficult and uncharted terrain, where no action is without

attendant risks, and success will not always be immediate. We need patience, perseverance and national cohesion if we are to succeed.

9. It has been alleged by some people that the reform programme has been dictated by the IMF and the World Bank. We are founder members of these two institutions and it is our right to borrow from them when we need assistance in support of our programmes. As lenders, they are required to satisfy themselves about our capacity to repay loans and this is where conditionality comes into the picture. All borrowing countries hold discussions with these institutions on the viability of the programmes for which assistance is sought. We have also held such discussions. The extent of conditionality depends on the amount and the type of assistance sought. However, I wish to state categorically that the conditions we have accepted reflect no more than the implementation of the reform programme as outlined in my letters of intent sent to the IMF and the World Bank, and are wholly consistent with our national interests. The bulk of the reform programme is based on the election manifesto of our Party. There is no question of the Government ever compromising our national interests, not to speak of our sovereignty.

10. Although the full fruit of our policies will take time to materialise, I am happy to report to the House that we have made substantial progress even in this short space of eight months. We have achieved our most immediate objective of restoring India's credibility and pulling the economy back from the slide into financial chaos. Our foreign exchange reserves have been rebuilt to about Rs. 11,000 crores. Non-Resident Indians are no longer withdrawing their deposits. We have successfully concluded arrangements with multi-lateral financing institutions such as the IMF, the World Bank and the Asian Development Bank to obtain quick disbursing funds to support the balance of payments in the current year.

11. Inflation remains a difficult problem, and one to which we attach the highest priority, because inflation hurts the poor and the fixed income earner most of all. Inflation was accelerating in June 1991, when our Government came to power, and the annual rate of inflation reached a peak of 16.7% in August 1991. Since then, the rate of inflation has come down to about 12%, but I am painfully conscious that this is still far too high. We are determined to bring inflation under control. This is why the Budget for 1991-92 focussed on the need for fiscal discipline. I am confident that as we persevere with fiscal discipline in 1992-93, and this we must do if we want to bring prices under control, the rate of inflation will come down substantially in the coming fiscal year.

12. Our ability to fight inflation has been considerably enhanced by the improvement in our foreign exchange reserves. This has enabled us to relax the restrictions imposed last year on imports, thus ensuring near normal availability of essential imports in the months ahead. This will help production and ease inflationary pressure. The comfortable reserves

position has also given the Government greater flexibility to finance additional imports of essential items to deal with shortages and break inflationary expectations.

13. The Government will remain fully vigilant on the prices front and will use the Public Distribution System to counter inflation and in particular to protect the poorer sections of the population from high prices and shortages. The Prime Minister announced on 1st January this year the launching of the revamped Public Distribution System in about 1700 of the most backward blocks of the country. We are determined to ensure that foodgrains and essential commodities reach the poor and the under-privileged in adequate quantities and at affordable prices.

14. Next to inflation, our major problem in the short term is the management of the balance of payments. We have averted collapse and gained some flexibility, but a sustained improvement in our external payments position requires much more. Our export earnings have suffered badly this year, mainly because of the disruption of trade with the former Soviet Union, and also because of recessionary conditions in world markets. As a result, we have not been able to finance our normal import requirements.

15. There are some who argue that all we need to do to solve our balance of payments problem is to compress our imports. I would like to point out that import compression has already been carried to the extreme and any further compression can only be at the cost of both growth and employment. Imports of non-essential consumer goods should certainly continue to be discouraged. However, we must recognise that the only lasting solution to our balance of payments problem lies not in compressing imports but in a rapid expansion of exports. A growing economy needs a growing volume of imports of fuel, and other industrial inputs and also of capital goods embodying modern technology. This is not to deny the importance of self-reliance, but self-reliance in today's world of integrated global markets cannot be achieved merely by reducing import dependence and insulating the economy from the world. Following that path will only lead to more import controls and promote inefficiency and corruption. It will perpetuate an environment in which Indian entrepreneurs will not have the flexibility they need to compete with other developing countries in world markets. The resulting inability to export will actually make us more, rather than less, dependent on the outside world. Our vision of a self-reliant economy should be of an economy which can meet all its import requirements through exports, without undue dependence on artificial external props such as foreign aid. I suggest to this august House that this is precisely the vision of self-reliance as bequeathed to us by Jawaharlal Nehru as elaborated in the Third Five Year Plan, and translated to the realities of today's world.

16. While introducing the new trade policy last year, Government had indicated that it would be our objective to move towards convertibility of the rupee on the current account. The achievement of convertibility is a sign of economic strength and true self-reliance. We are now ready to take the next

important step in this direction by introducing a new system of partial convertibility. The new system is designed to provide a powerful boost to our exports as well as to efficient import substitution. It will further reduce the scope for bureaucratic controls which contribute to both inefficiency and corruption. It will also greatly reduce the incentive for illegal transactions in foreign exchange. Under the new system all foreign exchange remittances, whether earned through exports of goods or services, or remittances, will be converted into rupees in the following manner : 40% of the foreign exchange remitted will be converted at the official exchange rate while the remaining 60% will be converted at a market determined rate. The foreign exchange surrendered at official exchange rates will be available to meet the foreign exchange requirements of essential imports such as petroleum and oil products, fertilisers, defence and life saving drugs. All other imports of raw materials, components and also capital goods will be made freely importable on open General Licence but the foreign exchange for these imports will have to be obtained from the market. There will be a specified "negative list" of raw materials, components and capital goods which will continue to be importable only against licences. There will be no change in the import policy for consumer goods which will remain restricted as at present. Foreign exchange required for other payments on private account including travel, debt service payments, dividends, royalties and other remittances will also have to be obtained at the market rate.

17. The new system will replace the system of Eximscrips. There will be no need to issue Eximscrips for each export transaction as the new system will operate through the banks. Instead of a premium on Eximscrips, exporters will have the benefit of the premium on 60% of their earnings in the foreign exchange market. What is more, the incentive for earning foreign exchange will now be available to remittances from our workers abroad. There is no reason why our workers, who earn foreign exchange by the sweat of their hard labour abroad, should be denied incentives presently given to exporters of goods and professional services. I salute our workers from Kerala and other states working abroad. What I have announced today is a small token of our appreciation of their magnificent contribution to India's foreign exchange earnings.

18. With these changes we will have achieved a major simplification of trade policy, eliminating licensing and the associated bureaucratic delays and inefficiencies over a wide range of items. We will also have introduced a self-balancing system to manage a large part of the balance of payments. The total volume of imports will be automatically regulated by the available volume of foreign exchange. Scarcity of foreign exchange will be reflected in a premium which will accrue to exporters and to those making remittances thus providing a built in incentive to increase this flow. The details of the new exchange system are being notified by the Reserve Bank of India. The changes in trade policy are being notified separately by the Commerce Ministry.

19. One of the reasons why foreign exchange is diverted to illegal channels is the illegal import of gold. It is time we took a bold step to recognise the

realities of the situation and legalise the import of gold. Government proposes to allow returning Indians and NRIs to import 5 kg. of gold per passenger with a modest import duty provided the gold as well as the import duty is financed from foreign exchange earned abroad.

20. Many Honourable Members of this House have suggested that the Government should introduce a Gold Bond, which would help to mobilise the idle gold resources of ordinary citizens to supplement official reserves. I had indicated in Parliament that this should be considered only when the balance of payments situation improves, and adequate confidence has been built in the capacity of the Government to manage the economy. This has now been achieved. Our reserves are large and do not need supplementing, but I see no reason why patriotic citizens should be denied the opportunity to contribute their mite to the development of India's economy. I propose to introduce a scheme under which citizens can obtain a Gold Bond in return for gold. The bond would be for a period of five to seven years and would be liquidated by return of gold, or equivalent value, at the option of the holder. It would enjoy a small interest, which will not attract income-tax. The bonds will also be free of wealth tax and gift tax. As an added incentive, holders of such bonds will not be asked any questions about the source of the gold holding. The Reserve Bank of India is preparing a detailed proposal along these lines.

21. One of the initiatives of the new Industrial Policy is a new approach towards foreign investment, which can play a vital role in upgrading our technology levels, integrating our industry into the global economy, and bringing in non-debt resources. The Government proposes to actively encourage foreign investment in critical infrastructure sectors where capacities are inadequate and needs for investment are large. A policy to encourage private investment, including foreign investment, in the Power sector has already been announced. Another area which is critical for our future development, and for management of the balance of payments, is the hydro-carbon sector. Government has already announced that joint ventures will be permitted in both exploration and development, including development of existing fields. The Government will welcome proposals for private investment, including foreign investment, in production, refining and marketing of oil and gas, with a view to maximising the growth potential of this crucial area.

22. Concern is sometimes expressed that the policy of welcoming foreign investment will hurt Indian industry and may jeopardise our sovereignty. These fears are misplaced. We must not remain permanent captives of a fear of the East India Company, as if nothing has changed in the past 300 years! India as a nation is capable of dealing with foreign investors on its own terms. Indian industry has also come of age, and is now ready to enter a phase where it can both compete with foreign investment and also cooperate with it. This is the trend all over the world and we cannot afford to be left out. The House can rest assured that we have enough policy instruments at our disposal to ensure that enterprises with foreign

equity function in accordance with our national priorities.

23. The new approach to industrial policy calls for a review of regulations such as the Foreign Exchange Regulation Act, which introduced a great deal of detailed administrative control over companies where the foreign equity exceeded 40% and also on non-resident Indians. The Reserve Bank of India has recently liberalised the procedure by granting general exemption from several of these controls applicable to Indian companies with foreign equity and to non-resident Indian returning to India. There are other restrictions which prevent Indian companies and Indian residents from entering into various types of commercial relations with companies abroad without prior approval. These provisions are out of line with the needs of today's economy, where Indian business will have to deal extensively with their counterparts abroad, requiring expeditious decision making. The Government proposes to introduce comprehensive amendments to the Foreign Exchange Regulation Act to bring it in line with the requirements of the new policy.

24. In my Budget speech last year I had referred to the importance of financial sector reform and had announced the establishment of a Committee on the Financial System. The Narasimham Committee has submitted its report which has been tabled in Parliament. While commending the progress made by the banking system in several directions, the Committee has drawn attention to serious problems posed by the deterioration in the financial health of the system because of low profitability, poor portfolio quality and inadequate provisioning for bad debts. The Committee has made comprehensive recommendations for reform covering all aspects of banking, including the introduction of better capital adequacy norms, better provisioning for bad debts, rationalisation of the provisions for directed lending and the associated interest rate structure. The thrust of the Committee's recommendations is to move to a more efficient and competitive banking system including a larger role for the private sector. Many of the recommendations can be implemented very quickly. Others need further consideration. The Government proposes to implement the recommendations of the Committee in a phased manner.

25. As a first step in implementing the recommendations of the Narasimham Committee, the Government has decided to begin a phased reduction in the Statutory Liquidity Ratio (SLR) which at present locks up large quantities of bank funds in relatively low yielding Government securities. Accordingly, the SLR on incremental domestic liabilities of the commercial banks is being reduced from 38.5% to 30% with effect from 1992-93. This reduction is in line with the proposed reduction in the fiscal deficit, which will reduce the Central Government's need to borrow from commercial banks. It will release funds for banks to expand credit to agriculture and industry. The market borrowing of the States will not be affected. Steps are also being taken to develop an active market for Government securities which will make

Government less dependent on statutory borrowing from the banks in future

26. In view of the decline that has already taken place in the rate of inflation, it is possible to provide some relief in the interest rates charged by the Banks on commercial advances. Honourable Members will be pleased to know that the Reserve Bank of India is separately notifying a reduction in the floor level of interest rates on commercial advances by one percentage point.

27. Financial sector reforms also includes reforms of the capital markets, which will increasingly play a vital role in mobilising and allocating resources from the public. Several initiatives announced in my Budget speech last year have since been implemented. The Securities and Exchange Board of India (SEBI), has now been established on a statutory basis. As we gain experience, additional powers will be given to SEBI to strengthen its capability. The Government has also issued guidelines which will govern the operation of new private sector mutual funds. Government has also decided to give permission to companies with a good track record to issue convertible debentures or equity to investors abroad and to extend to these issues the same tax benefits as are available for Offshore Mutual Funds. This will enable domestic companies to tap the large pool of equity funds available in world capital markets. We will also consider ways of allowing reputable foreign investors, such as pension funds, to invest in our capital markets, with suitable mechanisms to ensure that this does not threaten loss of management control.

28. The role of the Controller of Capital Issues in the Finance Ministry needs to be reviewed, especially in the context of the emerging industrial and financial scenario. The practice of Government control over capital issues, as well as over pricing of issues, has lost its relevance in the changed circumstances of today. It is therefore proposed to do away with Government control over capital issues including premium fixation. Companies will be allowed to approach the market directly provided the issues are in conformity with published guidelines relating to disclosure and other matters related to investor protection. Government proposes to bring necessary legislation to implement this decision.

29. In presenting the Budget for 1991-92 I had announced the Government's intention to establish a National Renewal Fund with the objective of ensuring that the cost of technological change and modernisation not fall too heavily on the workers. This Fund was intended to provide a social safety net which would protect the workers from the adverse consequences of technological transformation. The Government has now established the Fund. The Fund will provide assistance to cover the cost of retraining and redeployment of labour arising as a result of modernisation and restructuring, and also provide compensation to labour affected by restructuring of an industrial unit. Government also proposes to approach multinational financial institutions to meet part of the requirement for the National Renewal Fund. It is estimated that about Rs. 1000 crores would be available

from the International Development Association to be used for social safety net schemes under the Fund including special schemes or unorganised sector workers. In this context we would work out a scheme to upgrade the technology of handicrafts which employ a very large number of people in the decentralised sector. Honourable Members may rest assured that the Government is firmly resolved to protect the interests of labour while dealing with the problems of industrial sickness and structural reforms.

30. Agriculture is the foundation of our national prosperity and no strategy of economic development can succeed in our country if it does not ensure rapid growth of production and employment in agriculture. Nor can we hope to provide sufficient jobs for our growing rural labour force unless we can transform the economy of our rural areas. This calls for a multi-pronged strategy involving effective implementation of land reforms, large investments in irrigation and drainage, improvement in water management systems, control of land degradation, strengthening of the credit system and improvements in agricultural extension and research. Much of this effort has to be made by the State Governments since Agriculture is a State subject, and it is our hope that State Governments will give these issues the highest priority. The Centre on its part is firmly committed to continued funding and revamping of the various poverty alleviation schemes, which are major element in our development strategy.

31. Special attention needs to be paid to supporting innovative ideas for generating income and employment in rural areas through support to various types of agri-business. As an experimental measure, Government proposes to set up a Small Farmers' Agri-Business Consortium as an autonomous corporate entity funded by the Reserve Bank of India, NABARD and IDBI. The Consortium will include representation from various Development Boards dealing with individual crops and Public Sector Corporations dealing with agriculture and agro-industries, private sector companies, banks, scientific organisations and farmers' associations. The Consortium will function on the principles of economic efficiency, environmental soundness and social equity and will organise 12 major projects in 1992-93 in different parts of the country, based on a mix of enterprises with active participation by State Governments and farm families. The programme will be expanded as we gain experience. We must begin a new chapter in our agricultural history where farm enterprises yield not only more food, but more productive jobs and higher income in rural areas.

32. I now turn to the Revised Estimates for 1991-92. Our major macro-economic objective in 1991-92 was to reduce the fiscal deficit in order to restore macro-economic balance in the economy. I am happy to inform the House that we have succeeded in this objective.

33. The Budget Estimates for 1991-92 provided for a total expenditure of Rs. 113,422 crores. Unlike in the past, when Revised Estimates of expenditure showed substantial increase over Budget Estimates, this year they are marginally lower by Rs. 320 crores.

On the revenue side there has been a large shortfall of Rs. 3760 crores in customs revenue owing to the severe import compression during most of the year, but this has been partially offset by higher realisation from excise duties and income tax so that the shortfall in gross tax revenue is Rs. 1869 crores. The non-tax revenues and capital receipts are also significantly higher. As a result total receipts are estimated at Rs. 106,070 crores which is higher than the Budget Estimates of Rs. 105,703 crores.

34. The Budget deficit in the Revised Estimates for 1991-92 is Rs. 7032 crores which is lower than the Budget Estimate of Rs. 7719 crores, and much lower than in 1990-91, when the budget deficit reached Rs. 11,347 crores. The fiscal deficit, which takes into account all borrowing, is Rs. 37,792 crores in the Revised Estimates. This is almost identical to the figure of Rs. 37,727 crores in the Budget Estimates, and is much lower than Rs. 44,650 crores in 1990-91. With this, we have successfully reduced fiscal deficit from about 8.4% of GDP in 1990-91 to around 6.5% in 1991-92.

35. The reduction in the deficit was made possible by enforcement of strict discipline on the expenditure side. Certain additional expenditure provisions became necessary after the Budget was presented. The most notable of these was the additional requirement for fertiliser subsidy, consequent on the decision to restrict the price increase from 40% proposed initially to only 20%, and also the fact that the rupee cost of imported fertiliser was higher than assumed in the Budget Estimates. As a result, the provision for fertiliser subsidy has been increased from Rs. 4000 crores in the Budget Estimates to Rs. 4800 crores in the Revised Estimates. Even this amount does not fully cover the subsidy claims for 1991-92 and some amount will spill over into the next year as is normal commercial practice. A separate provision of Rs. 405 crores has been included in the Revised Estimates for the scheme for supplying fertilisers to small farmers at the pre-revised prices.

36. I have also had to increase the Budget provision for food subsidy by Rs. 250 crores on account of the delay in increasing issue prices. An extra amount of Rs. 550 crores has also been provided for the export subsidy. This subsidy was abolished on 3rd July, 1991, but the claims in the pipeline appear to be much more than was originally anticipated. These demands for additional expenditure have however been offset by savings located within the sanctioned Budgets of various Ministries.

37. The difficult resources position in 1991-92 had its impact on Plan expenditure. Overall resources constraints forced the Government to restrict Budget support for the Central Plan and the Revised Estimates for this item are 7% less than Budget Estimates. Despite the marginal reduction, efforts were made to ensure that projects of high priority are not affected, and the reduction has been achieved mainly by regulating the release of funds to match the actual progress of schemes on the ground. However, Central Assistance for State and UT Plans was stepped up by Rs. 651 crores, mainly on account of larger rupee requirements of externally aided projects.

38. The House will be happy to note that even though the Central Government's own expenditure in the Revised Estimates is below the Budget Estimates, the total transfer to the States by way of share of taxes, and Central Plan assistance is higher than the Budget Estimates by Rs. 1683 crores. This more than offsets the shortfall in small savings loans of Rs. 1365 crores. We have not allowed our fiscal difficulties to come in the way of meeting our obligations to the States in any way.

39. I now turn to the Budget Estimates for 1992-93. The Eighth Five Year Plan commences from 1st April 1992 and aims at the objectives of achieving near full employment in a period of ten years. The investment requirements of every sector are large, and it is important that Plan allocations should enable implementing agencies to make a good start, especially in the infrastructure sectors. However we have had to work within the limits imposed by the continuing need to restore macro-economic balance, which is essential if we are to contain inflation and manage the balance of payments. This calls for a further reduction in the fiscal deficit in 1992-93. Larger Plan expenditure can be accommodated within a smaller fiscal deficit if, apart from increasing tax and non-tax revenues, Government's non-Plan expenditure can be contained. I must admit that this has been a daunting task.

40. Interest charges are the largest single item of non-Plan expenditure and account for Rs. 32,000 crores in the Budget Estimates for 1992-93. This represents an increase of Rs. 4750 crores over the Revised Estimates for 1991-92, which is larger than the increase in total non-plan expenditure of Rs. 4405 crores. This means that in 1992-93 all other items of non-Plan expenditure taken together are actually lower than in the current year. Honourable Members will appreciate that interest charges are a committed expenditure, reflecting the cumulative effect of past deficits. This item can be controlled only by reducing the reliance on borrowed funds, and I intend to do this by reducing the fiscal deficit for 1992-93. However, the benefit of this action will be felt only by Finance Ministers presenting the Budget in future. I venture to think that my successors as Finance Minister will be able to sleep far more peacefully than has been my lot thus far.

41. For the Defence Services I am providing Rs. 17,500 crores, an increase of 7% over the provision of Rs. 16,350 crores in the current year. Combined with some economies and tight expenditure control, I am confident that this allocation will enable our armed forces to fulfil their responsibilities in ensuring the security and defence of the nation.

42. In the election Manifesto of our Party, we had committed ourselves to find an innovative solution to the long standing demand of Defence pensioners for "One Rank One Pension". An empowered Committee, under the chairmanship of Raksha Mantri and comprising ex-servicemen and Members of Parliament representing the major political parties has looked into the issue and its recommendations have been accepted by the Government. Accordingly,

Government has sanctioned adhoc increase in the pension rates applicable to Defence personnel. This decision effective from 1-1-92 will benefit over six lakh Armed Forces pensioners of all ranks, of whom over two lakhs are Jawans, some of whom retired after 1-1-86. Government has also ordered grant of ex-gratia Family Pension to the families of deceased Reservists not in receipt of Family Pension. These benefits will entail an expenditure of over Rs. 120 crores per annum at current rates of dearness relief.

43. Subsidies are another important component in non-Plan expenditure. Last year, Food, Fertiliser and Export subsidies were the three major subsidies and their rapid growth has been one of the main factors behind the unchecked growth of non-Plan expenditure. We made an important change this year by abolishing export subsidies. However, some subsidy payments still remain in the pipeline, and I am providing Rs. 480 crores on this account.

44. Food subsidy is a part of our system of food security for the poorer and weaker sections of our population and is a basic element in our social policy. I am providing an allocation of Rs. 2,500 crores on this account which should be sufficient for the normal requirements of the system. The revamped Public Distribution System being implemented in 1700 backward blocks will require an additional allocation of Rs. 250 crores on account of the additional subsidy and also the cost of constructing a large number of godowns with a capacity of 3 lakh tonnes. The allocation for these items will be augmented in the course of the year to meet the requirements fully.

45. This brings me to fertiliser subsidy which has grown into the largest single subsidy in our system. There is no doubt that fertiliser is an essential ingredient for agricultural production, and agricultural development is vital not only for economic growth in general, but also to ensure rising levels of income and employment in rural areas. In 1980-81, the fertiliser subsidy was 12% of the total allocation in the Central and State Plans taken together for Agriculture, Rural Development, Special Area Programmes and Irrigation and Flood Control. It increased to 33% in 1991-92. A Parliamentary Committee is currently looking into the whole issue of fertiliser pricing and subsidy including alternatives for restructuring the subsidy. I propose to wait for the report of this Committee and take a view, on this matter later in the year. Taking all factors into account, I am making a provision of Rs. 5000 crores for fertiliser subsidy in 1992-93.

46. Other items of non-Plan expenditure have been tightly constrained in the allocations provided to keep the fiscal deficit within manageable levels. I have requested my colleagues in all Ministries to review the expenditure control system in their Ministries to ensure that every possible step is taken to enforce economy so that the provisions being made in the Budget Estimates are not exceeded. As in the last two years, in the Budget Estimates for 1992-93 also no separate provision is being made for the additional dearness allowance instalments that may become payable in that year. All Ministries will be expected to absorb the additional expenditure on this account within the approved Budget provisions.

47. With these provisions, the total allocation for non-Plan expenditure stands at Rs. 84,475 crores, higher by Rs. 4,405 crores compared to the Revised Estimates for 1991-92. But then, as I mentioned earlier, the increase in interest expenditure alone is Rs. 4,750 crores. Honourable Members would appreciate that the large requirements for interest and subsidies make it difficult to reduce non-Plan expenditure further and this limits the extent to which the budget can support Plan expenditure. Nevertheless, I have tried to provide adequately for all critical areas of Plan expenditure.

48. Central assistance for the Plans of States and Union Territories is being stepped up from Rs. 14,710 crores in Budget Estimates 1991-92 to Rs. 16,111 crores in 1992-93. This increase of Rs. 1,401 crores, coupled with an increase of Rs. 2,237 crores in the share of taxes, even at the existing levels of taxation, should enable the States to substantially increase the allocations for the various Plan programmes.

49. The total Central Sector Plan outlay for 1992-93 has been fixed at Rs. 48,407 crores. This is based on budgetary support for the Plan of Rs. 18,501 crores, and a contribution of Rs. 29,906 crores from internal and extra-budgetary resources of the various undertakings/enterprises. The internal and extra-budgetary resources show a sharp increase of 25% over the current year's level and this is critical to achieve the substantial increase in the Plan outlays of the various infrastructure sectors. Thus the outlay for the Railways stands increased from Rs. 5,325 crores in the current year's Budget Estimates to Rs. 5,700 crores in the next year's Plan; Shipping from Rs. 617 crores to Rs. 1,222 crores; Civil Aviation from Rs. 433 crores to Rs. 1,036 crores; Telecommunications from Rs. 3203 crores to Rs. 4,500 crores and Fertiliser industry from Rs. 411 crores to Rs. 1,234 crores. The outlay for Power has been fixed at Rs. 6,411 crores, and for Petroleum at Rs. 6,054 crores.

50. The allocation for Rural Development Programmes in the Budget is Rs. 2,610 crores, which is somewhat lower than the Budget Estimates of 1991-92 though it is higher than the Revised Estimates. This however presents only part of the total effort we are making in support of the weaker sections in our rural areas. The Government is deeply conscious of its special responsibility to protect the poorer sections of our society, especially in rural areas from the burdens that would otherwise be forced upon them as the economy goes through the process of macro-economic stabilisation and economic restructuring. It is therefore proposed to earmark an additional allocation of Rs. 500 crores from the corpus of the National Renewal Fund for employment generation schemes to supplement the normal employment generation through the Jawahar Rozgar Yojana, particularly in those areas where the pressure for such employment is seen to be more than in earlier years. The additional allocation of foodgrains, through the Public Distribution System in the 1,700 most backward blocks at a subsidised rate is another important step for protecting these vulnerable sections of society from the pressure on prices. Taking the proposed additional allocations on these accounts together with the Plan provision in the Budget, the

total allocation to rural development would show a substantial increase over the current year.

51. The Plan outlay for the Family Welfare programme has been stepped up from Rs. 749 crores in the current year to Rs. 1,000 crores next year reflecting the Government's firm commitment to tackle the population problem. The outlay for the programmes of the Ministry of Welfare has also been increased from Rs. 479 crores to Rs. 530 crores reflecting fully Government's commitment to protection of the weaker sections of society.

52. Despite severe resource constraints, most of the other sectors which are largely dependent on budgetary support for their Plan outlays have been provided at least the same order of budget support as in the current year. I would like to provide more but we also have to live within the constraint of available resources. I would particularly like to point out that we must give up the practice of judging the quality of our Plan effort by the increase in the outlays provided for in the Budget. Our resources are scarce and there is a vast unexploited potential for improving the productivity of available resource use. There has to be much tighter scrutiny of various claims on resources and much greater emphasis on how to get more out of available resources. We cannot simply spend our way into prosperity.

53. Gross tax receipts at existing rates of taxation are estimated next year at Rs. 75,541 crores compared to Rs. 67,300 crores in the current year's Revised Estimates. The States' share of taxes is placed at Rs. 18,492 crores showing an increase of Rs. 1,293 crores over the current year's Revised Estimates. Non-tax revenues next year show an increase of Rs. 2,689 crores over the current year's Revised Estimates. This includes Rs. 416 crores of deferred dividends from the Railways. Next year's estimates assume an increase of Rs. 423 crores from dividends and profits of public sector enterprises. Unlike in the past, it is proposed to ensure that these enterprises transfer as dividend or surplus profits, a reasonable part of their post tax profits instead of determining the dividend payable merely on the basis of capital investment. The Reserve Bank of India will also be transferring a larger share of its profits.

54. Under Capital Receipts, I have taken credit for market borrowing of Rs. 5,000 crores. This is significantly lower than the amount of Rs. 7,500 crores in the Budget Estimates for the current year and reflects our objective of reducing the fiscal deficit and consequently the recourse to borrowed funds. External assistance including grants, but net of repayments, is estimated at Rs. 5374 crores.

55. The disinvestment in public sector equity undertaken in the current year has been successfully completed. There is scope for continuing this process in 1992-93 with a view to raising non-inflationary resources for development. I am accordingly taking credit for a receipt of Rs. 2,500 crores from further disinvestment of equity holding in public sector enterprises. In addition to this amount, Government will consider a further sale of equity of Rs. 1,000 crores to provide resources to the National Renewal Fund in

1992-93, which can be used for various schemes of assistance to workers in the unorganised sector, including women workers, who may be adversely affected by the process of economic restructuring. These resources will also be used to fund the special employment creating schemes in backward areas which I have mentioned earlier.

56. Thus, at existing rates of taxation, total receipts are placed at Rs. 114,215 crores and total expenditure at Rs. 119,087 crores. This leaves a gap of Rs. 4872 crores.

## PART B

57. While presenting the budget last year, I drew attention to the need for a comprehensive reform of both the direct and indirect tax system and had explained that lack of time had made it difficult to do as much as I would have liked in this regard. Subsequently, the Government set up a Tax Reforms Committee under the Chairmanship of Dr. Raja J. Chelliah. The Committee has since submitted its Interim Report. The Report distills the wisdom of some of our most distinguished experts on the complex subject of reform of both direct and indirect taxes and I have drawn heavily upon it in framing my Budget proposals. The summary of recommendations contained in the Report is separately being placed in Parliament to enable fuller appreciation of the analysis of the Committee and the rationale for its recommendations.

58. There is a consensus among fiscal experts, based on experience gained all over the world, that a moderately progressive tax structure combined with strong enforcement is the best way of encouraging honesty and voluntary tax compliance. The Chelliah Committee has endorsed this view and has recommended that our direct tax system would be more effective if the income tax regime had lower rates of taxation, with a narrower spread between the entry rate and the maximum marginal rate, and a minimum of tax incentives. I agree with this assessment and I propose to restructure the personal income tax in the following manner. I propose to enhance the exemption limit for income tax levy from Rs. 22,000 at present to Rs. 28,000. This will provide substantial relief to the taxpayers in the lower income group and I am sure it will be welcomed by the Honourable Members, many of whom had urged such an adjustment even last year. I hope this will convince them that I am an attentive and sensitive listener to what goes on in this august House. I further propose that there will only be three tax rate slabs, with the entry rate of 20 per cent, applicable upto Rs. 50,000, a middle slab of 30 per cent upto Rs. 1,00,000 and a maximum rate of 40 per cent, above Rs. 1 lakh. A corresponding revision is also being made in the case of specified Hindu undivided families. Because of the severe resource constraints, I am compelled to retain the surcharge at 12 per cent for one more year, but this will be payable only by those whose income exceeds rupees one lakh.

59. With the reduction in tax rates, a number of tax exemptions, which conferred large benefits on higher income tax payers are no longer justified. I, therefore, propose to abolish the deductions under sections 80L, 80CCA and 80CCB of the Income-tax Act.

561 GI/92-5

The computation of income from house property is also being rationalised in respect of certain deduction presently being allowed. The provision under section 88, which provides for tax rebate in respect of specified savings such as Life Insurance, Provident funds etc., will however continue, as these are normally availed of by fixed salary earners. In fact, I propose to widen its scope by including within its purview contributions to Pension Funds set up by the National Housing Bank and by Mutual Funds. I am also providing that those who wish to continue contributing to the savings schemes which until now qualified for deduction under section 80CCA and 80CCB, can get tax rebate under Section 88 of the Income-tax Act.

60. It is said that the child is the father of man, but some of our taxpayers have converted children into tax shelters for their fathers. The tax law provides for clubbing of income from gifts given by parents but this does not apply to other income, including income from other gifted assets, and the practice of cross gifting is widely used to evade clubbing. The Chelliah Committee has recommended that in order to plug this loophole, which accounts for a substantial leakage of revenue, the income of a minor child should be clubbed with that of the parent. There is merit in this suggestion and I propose to accept it. Recognising however the existence of a number of child prodigies, especially child artiste in our country, I propose to exclude their professional income, as also any wage income of minors, from the purview of such clubbing. The practice of clubbing the income of minor children with that of the parent for tax purposes is in vogue in a number of countries.

61. The revenue loss on account of the restructuring of income-tax rates as traditionally estimated will be Rs. 1500 crores. However, this will be offset by the proposed abridgement in the concessions and tax exemptions and the change in the tax treatment of minor's income. If, as I expect, lower tax rates will lead to better tax compliance, there will be a net revenue gain even though it is not possible to quantify it. If tax-payers cooperate with me and revenue earnings go up significantly, I propose to reward the tax-payers with a further cut in income tax rates. The ball is now in their court.

62. In a country with a population of over 800 million, hardly 7 million persons pay income and corporate tax. It is therefore necessary to attract new tax payers into the tax net. With this end in view, I propose to introduce a presumptive tax system in respect of shop keepers and other retail traders with an annual turnover below Rs. 5 lakhs. In order to enable them to avoid the difficulty of maintaining detailed account books, filing a complicated tax return and going through the normal assessment procedure, a simplified scheme has been worked out under which the taxpayer will give only brief particulars of his turnover and pay just Rs. 1400 as tax for that year. This should enable potential taxpayers in this category to overcome their psychological hesitation of getting into the tax system. The scheme is being introduced on a purely optional basis and is intended only for those who may have taxable income and wish to avail of this simplified

procedure. With the increase in the exemption limit to Rs. 28,000, those with a turnover of less than Rs. 2.5 lakhs to Rs. 3 lakhs may well find that they do not have to pay this presumptive tax.

63. The present tax treatment of long term capital gains has been criticised on the ground that the deduction allowed in computing taxable gain is not related to the period of time for which the asset has been held. It does not take into account the inflation that may have occurred over time. The Chelliah Committee has suggested a system of indexation to take care of the problem and I propose to accept its recommendation. Taxable capital gains will be computed by allowing the cost of the asset to be adjusted for general inflation before deducting from the sale proceeds. The adjustment factor for each year will be notified by the Central Government. The long term capital gains thus computed will be taxed at 20 per cent in the case of individuals and HUFs, 40 per cent. in the case of companies, firms, associations of persons and bodies of individuals, and 30 per cent. in the case of others. The new system will favour those whose capital gains accrue over a longer period, while those making capital gains over a shorter period will pay a higher tax. This is as it should be. The cut off date for valuation is also being shifted from 1st April, 1974 to 1st April, 1981. With these changes, I propose to withdraw the standard deduction in computing taxable capital gains and also the exemptions under section 54E for capital gains invested in specified assets and section 53 in respect of capital gains arising from sale of residential house.

64.1 While I am simplifying the income-tax structure, I should extend some concessions directly to certain categories of taxpayers who deserve sympathetic consideration from the Government.

64.2 Many individuals have to maintain handicapped dependants which often imposes a heavy burden upon them and this is a burden which we should lighten as much as we can. I therefore propose to increase the deduction available to such persons from Rs. 6,000 at present to Rs. 12,000 per year. Further, the scope of this tax concession is being made available to all taxpayers irrespective of their income.

64.3 Women who take up employment deserve special consideration and encouragement. I, therefore, propose to increase the standard deduction from Rs. 12,000 to Rs. 15,000 in the case of working women having total income upto seventy five thousand rupees. I hope this will convince Honourable lady members of this House about my commitment to the cause of social and economic uplift of Indian women. The only quid pro quo I expect from them is to defend the budget regardless of their party affiliations.

64.4 Taking note of the financial difficulties often encountered by persons in old age and as a token of my regard for such senior citizens, I propose to give a tax rebate of 10 per cent. on the net tax payable by persons who have completed 65 years of age and whose gross total income is below Rs. 50,000.

64.5 Having regard to the fluctuating nature of income earned by authors, playwrights, artists, musicians, actors and sportsmen and in recognition of their contribution to the enrichment of the cultural life of the nation, the tax rebate for them in respect of specified savings under section 88 of the Income-tax Act will be increased from 20 per cent. to 25 per cent.

64.6 The victims of the Bhopal Gas Disaster are to get compensation on the basis of the Supreme Court judgement. Having regard to the human dimensions of the tragedy, I propose to exempt, in all cases, the compensation received by such recipients from income tax liability.

64.7 I have received several representations for widening the scope of exempting medical expenses for both salaried and self-employed persons. I propose to substantially liberalise the provisions relating to hospitalisation and medical insurance. Tax benefits to salaried persons will no longer be limited to treatment in a few government recognised hospitals only. Similarly, for self-employed persons, the deduction available for medical insurance is being enhanced from Rs. 3,000 to Rs. 6,000.

64.8 Exemption from income-tax is now available to the employees of the public sector on payments made under the Voluntary Retirement Schemes. I propose to extend the benefit of the exemption, subject to certain guidelines to the employees in the private sector as well.

65. There has been a long standing criticism that by subjecting the income of both partnership firms as well as the partners to taxation, we are engaging in double taxation. The Chelliah Committee has also stressed that double taxation in this regard should be avoided. I agree that we should avoid double taxation and I propose, as a measure of relief, to treat the firm as a separate tax entity and do away with the taxation of the same income in the hands of partners. I propose to allow deduction towards interest and salary payments made to partners from the income of the firm and then tax the balance income in the hands of the firm at a flat rate of 40 per cent. The proportion of deduction allowed decreases with the income level of the firm and is so designed that the total tax incidence on small firms and professional firms will be reduced. The partners will not be taxed on their share in the income of the firm though they will be liable to pay tax on salary and interest income. This method will result in enormous simplification from the point of view of taxpayers as well as tax administration as the proposed scheme will do away with complexities, associated with the procedure relating to registration of firms, rectification of partners' assessments when firms' assessments are revised, etc.

66. Last year, I introduced provisions relating to tax deduction at source in respect of interest on term deposits with banks and commission payments. There has, however, been considerable criticism from taxpayers about the implementation of these provisions. I have also received representations from a

number of Members of Parliament seeking withdrawal of these provisions. The system of tax deduction at source is a useful tool and one of the well recognised methods of enforcing tax compliance in many countries. However, a harassed Finance Minister has to be sensitive to the opinions of Honourable members of Parliament even when they differ from his own convictions. Therefore, I propose to withdraw these two provisions.

67. The Wealth-tax Act, 1957 has far too many exemptions making its administration enormously complicated. The valuation of certain assets such as shares also presents problems since very high market values reflecting speculative activity can lead to a heavy burden on shareholders who are long term investors. There is also no distinction at present between productive and non-productive assets. The Chelliah Committee has suggested that in order to encourage the taxpayers to invest in productive assets such as shares, securities, bonds, bank deposits, etc. and also to promote investments through Mutual Funds, these financial assets should be exempted from wealth tax. Wealth tax should be levied on individuals, Hindu undivided families and all companies only in respect of non-productive assets such as residential houses including farm houses and urban land, jewellery, bullion, motor cars, planes, boats and yachts which are not used for commercial purposes. The Committee has further suggested that such tax should be at the rate of one per cent., with a basic exemption of Rs. 15 lakhs. I propose to accept this recommendation and I hope this change will encourage investments in productive assets and discourage investment in ostentatious non-productive wealth.

68. Earlier in my speech I have referred to the importance which the Government attaches to the capital market and the special role of mutual funds including private sector mutual funds. In order to treat all mutual funds alike in tax matters, I propose to exempt from income tax mutual funds in both public sector and private sector recognised by the Securities and Exchange Board of India. I had also referred to the scheme permitting Indian Companies to issue convertible bonds and equity to investors abroad. I propose to tax the income and capital gains from these issues at a concessional rate of 10 per cent., as is applicable to Offshore mutual funds. It is hoped that these measures will give a new thrust to the capital market in the country.

69. Last year, I had extended expenditure tax to cover airconditioned restaurants in order to mop up additional resources. I have received several representations that this provision falls heavily on innumerable restaurants and small establishments which are patronised mainly by the middle class. It has been suggested that airconditioning in restaurants, unlike in homes, is no longer a luxury item of the rich. The largest number of such complaints have come from Bombay. Having lived in Bombay for two and a half years, I have special regard for the citizens of this great city. This has been reinforced by their voting behaviour in the recent elections to the Municipal Corporation. I, therefore, feel a

special obligation to respond. I propose to withdraw this levy as far as the restaurants are concerned. However, I have made certain changes in the scope of the Expenditure-tax Act relating to hotel receipts. I propose to enhance the qualifying limit for liability relating to room charges of the hotel from the present Rs. 400 per day to Rs. 1200 per day. In view of the exchange rate adjustments undertaken recently, there is no longer any need for exempting expenditure made in foreign exchange from the tax. I am, accordingly, withdrawing this exemption.

70. With a view to providing support to the cooperative sector, I propose to exempt all cooperative societies including urban cooperative societies engaged in the business of banking from the purview of Interest-tax Act.

71. I recognise the need for a reform of the corporate tax system. This is also an area where rates of taxation need to be lowered and I would like to give advance notice of my intention to begin lowering them as soon as possible. However, as the detailed recommendations of the Chelliah Committee on corporate taxation are yet to be received, I propose to defer major restructuring in this area until after I have received its recommendations. Accordingly, for the present there will be no change in the rate structure as well as the surcharge. In this budget, I propose to make just two changes. Ordinarily, depreciation and investment allowance carried forward from earlier years is set off against the current income. In line with the rationalisation of depreciation allowance brought about last year, I propose that in respect of assessment year 1992-93, the quantum of set off for carried forward depreciation and investment allowance in the case of companies, where such amount exceeds Rs. 1,00,000, shall be limited to two-third of such amount and the remaining one-third will be allowed to be adjusted in the assessment year 1993-94. Further, having regard to the widespread criticism that the Income-tax Act has artificial ceilings in regard to certain business expenses, I am liberalising some of the items on the basis of the recommendation of the Chelliah Committee.

72. Having regard to the complexities in tax laws, I have been receiving representations that the Government should give Advance Rulings whenever a taxpayer has doubts about the tax liability in respect of intended transactions. This practice obtains in a number of countries. There are certain practical difficulties in implementing such a suggestion. However, in the interest of avoiding needless litigation and promoting better taxpayer relations, a scheme for giving Advance Rulings in respect of transactions involving non-residents, is being worked out and will be put into operation soon. The scope of this can be extended subsequently on the basis of experience gained. The Government is also planning to set up the National Court of Direct Taxes in order to ensure that litigation in direct tax matters is settled expeditiously. Along with this, the Government would also like to bring forward, as soon as possible, a Bill on Direct Taxes Code, integrating therein all the three direct taxes so as to make the law easily understandable and tax administration simple.

73. I do not propose to take up the time of the House with other minor changes in the Direct Tax Laws.

74. My proposals on direct taxes are estimated to yield a net revenue gain of Rs. 795 crores. Of this amount, Rs. 435 crores will accrue to the States.

75. I now turn to the proposals relating to indirect taxes.

76. A long standing complaint of our industry, and of experts in trade policy is that our customs tariff rates are too high and increasingly out of line with the trends in our competitor countries, all of whom have reduced tariffs to very moderate levels. My colleague the Honourable Commerce Minister has repeatedly told me that we cannot expect to compete with these countries in world markets if we persist with high tariff rates which have the effect of creating a high cost industrial structure. This is in line with the directions I had indicated in my budget speech last year. The Chelliah Committee, which was asked to look into all aspects of customs duties has recommended reduction in the general level of tariffs, a reduction in the dispersion of the tariff rates and a rationalisation of the system with abolition of numerous end-use exemptions and concessions. The Committee has also rightly suggested that the process of reform should be gradual, so as to moderate the impact of the adjustment, both in terms of possible revenue loss and the pace at which domestic industry is exposed to competition. I propose to act on these recommendations by making a substantial start in this budget on reforming the customs tariff structure.

77. Last year I had begun the process of reducing import duties by lowering the ad valorem rates of basic plus auxiliary duties of customs to a maximum of 150%. I now propose to lower the peak tariff level further by reducing the basic plus auxiliary rates of import duties (inclusive of specific duties) to a maximum of 110% with the exception of passenger baggage and alcoholic beverages. The loss of revenue on account of this proposal as traditionally estimated is Rs. 1700 crores, though I feel it could be much lower in practice.

78. My next proposal relates to the duty on capital goods. The general duty on capital goods, including project imports, is currently at 80% which is below the peak rate of 110%. However, there is a good case for giving priority to reducing the duty on capital goods because high duty on capital goods constitutes a permanent increase in the cost of production for the life of the unit. In order to encourage new investment in export oriented industries, we should move to a lower duty rate on capital goods at an accelerated rate. I, therefore, propose to reduce the duty rate on project imports and general machinery from 80 per cent to 60 per cent. In the case of capital goods including project imports for electronics industry, I propose to reduce the import duty from 60 per cent to 50 per cent. In relation to capital goods for projects of coal mining and crude petroleum refining, I propose a deeper reduction in the import duty prescribing a uniform rate of 30 per cent. In the case of power

projects, the present concessional duty rate of 30 per cent or 40 per cent is being rationalised to a uniform rate of 30 per cent. I also propose to reduce the import duty on other capital goods currently attracting duty above 80 per cent by 10 percentage points. The existing concession in the duty rates available to the components of specified machinery enabling those items to be imported at rates below the rate applicable to the machinery is proposed to be continued. These changes will not adversely affect the competitive position of the Indian capital goods industry especially in view of the exchange rate adjustment effected last year. These proposals involve a loss of revenue of about Rs. 840 crores.

79. In view of the reduction of tariff peaks, I have also taken the opportunity to remove some of the end-use notifications for concessional duty imports. In this process of rationalisation, some duties may go up marginally. However, in view of the overall reduction of duty rates, industry should be able to absorb such marginal increases.

80. In my last budget I had proposed certain rationalisation of the rates of auxiliary duty of customs. I propose to further rationalise the auxiliary duty structure by reducing the number of duty slabs to four. The loss of revenue on this account is estimated at Rs. 125 crores.

81. Agriculture is the bedrock on which our economic development depends and the vital inputs for this sector have always been accorded a preferential tax treatment. In line with this principle, I propose to reduce the duty rate on 15 specified pesticides from 110% at present to 75%, by adding them to the list of pesticides eligible for this concession. I also propose to reduce the import duty on two pesticide intermediates from the present level of 12% to 65%. So also I propose to exempt three specified pesticide intermediates completely from excise duty. These proposals involve a revenue loss of about Rs. 8 crores.

82. Successful agricultural development calls for injection of new seeds which can increase productivity and imported seeds and planting material can help in this process. I, therefore, propose to fully exempt from import duty, oil seeds, seeds of vegetables, flowers and ornamental plants; tubers and bulbs of flowers; cuttings or saplings of flower plants; and seeds of fruit-plants and pulses, for the purpose of sowing and planting. In order to ensure efficient transplanting of seedlings, I also propose to reduce the import duty on rice transplanters from 80% to 40%.

83. The petro-chemical industry suffers from high duty rates on certain basic feedstocks which are the building blocks of the industry. There is a case for duty reduction and rationalisation in this area. I, therefore, propose to reduce the import duty on propylene from 120% to 80%, on butadiene from 55% to 40% and on benzene from 40% to 25%. I also propose a uniform import duty of 40% for ethylbenzene and styrene which are essential inputs for the manufacture of polystyrene. Similarly, I

propose to reduce import duty on certain specified feedstocks which find use in the manufacture of polyethylenes from 120% to 40%. The loss of revenue on account of the proposals would be around Rs. 26 crores.

84. As a measure of relief to the asbestos cement industry which serves the housing, water supply and irrigation sectors, I propose to reduce the import duty on asbestos fibre from 90% to 70%. The proposal involves a loss of revenue of Rs. 18 crores.

85. Films in our country have become an important vehicle of national integration. I have therefore to worry about the economic health of this important industry. In order to give relief to the film industry, which is facing increasing competition from cable TV and video, I propose to reduce the import duty on unexposed colour negatives of cinematograph film by 20 percentage points from the existing level. The loss of revenue involved in the proposal is Rs. 8 crores.

86. I propose to reduce the import duty on specified items of machinery required for the manufacture of fly ash and phosphogypsum bricks and building components.

87. Last year as a relief to the newspaper industry I had exempted standard newsprint fully from customs duty. I feel my support base in the Press could do with some strengthening. I now propose to fully exempt glazed newsprint which is presently attracting import duty of Rs. 550 per metric ton from payment of duty. The proposal involves a revenue loss of about Rs. 3 crores.

88. I have already mentioned that import of gold by Indians including persons of Indian origin as part of their baggage will now be allowed. Every such passenger will be allowed to bring upto five kilograms of gold and the import duty on such gold will be Rs. 450 per 10 grams, which works out to about 15% *ad valorem* terms. This duty will be payable in convertible foreign exchange. I am confident that this step will be welcomed by all, except those engaged in the hitherto profitable business of smuggling this metal into the country.

89. The restructuring of customs duty being attempted in this Budget is the beginning of a process in which our customs duties are gradually reduced, over a three to four year period, to levels comparable with those in other developing countries. I would like to reassure Honourable Members that they need have no fear that the process of reducing duties will lead to the deindustrialisation of India. On the contrary, the reduction is necessary to give the Indian industry an environment in which it can increase its competitiveness through absorption of technology and greater integration with the world economy. This is essential if we are to achieve true self reliance. We shall take effective promotional measures to build up the competitive strength of Indian industry. The proposed restructuring of customs duty, together with the other changes in customs duty results in a net loss of Rs. 2023.35

crores. The loss is estimated in the conventional way and it is possible that it may be overestimated if we allow for a substantial improvement in the balance of payments, permitting a larger volume of imports and, therefore, a higher level of customs revenue.

90. In the field of excise duties, I have been guided by the objectives of rationalising the excise duty structure, providing reliefs where necessary and, of course, raising additional resources to offset the revenue loss from restructuring of customs tariffs.

91. While presenting the budget for 1991-92, I had referred to my intention to rationalise and simplify the procedures, rules and regulations pertaining to indirect taxes so that the delays in the system are eliminated and the interface between the tax collector and the tax payer is reduced to the minimum. I propose to make an advance in this direction by abolishing licensing controls on production and manufacture under the Central Excises and Salt Act, 1944. The assessee would simply be required to register themselves with the central excise authorities. At present assessee are required to get their central excise licences renewed every five years. Registration will be valid as long as the assessee continues the manufacturing activity. I am proposing suitable amendments in the law to this end.

92. Honourable Members would be aware that a Settlement Commission was established in 1976 under the Income-tax Act, 1961. I propose to set up a Settlement Commission, on similar lines, for dealing with customs and central excise disputes between the Department and the assessee. I trust this will help in speedy settlement of tax disputes.

93. Honourable Members may also recall that a law was enacted in 1986 for the establishment of an appellate tribunal for the adjudication of disputes relating to the determination of the rates of duties of customs and central excise and to the valuation in pursuance of Article 323-B of the Constitution. Due to unavoidable reasons, the tribunal could not be established. I propose to introduce legislation to suitably amend the Customs and Central Excise Revenues Appellate Tribunal Act, 1986 and set up the tribunal.

94. The housing sector is important, both socially and for employment generation and as such deserves special treatment. I propose to fully exempt from excise duty bricks and tiles having a minimum content of 25% of red mud, which is a waste product of aluminium industry. I also propose to fully exempt light weight concrete building blocks from excise duty. Further I propose to reduce the excise duty on pre-fabricated buildings from 15% to 5%. I also propose to fully exempt doors and windows made of plastic, iron and steel which incidentally would conserve our dwindling forest cover. Further, I propose to exempt completely panel doors which are currently attracting 30% excise duty. The proposals involve a revenue loss of about Rs. 4 crores.

95. The glass container industry has been going through a lean period. I propose to reduce excise duty on glass containers from 40% to 30%. The excise duty on glass containers manufactured by semiautomatic process and mouth blown process will also be reduced from the existing levels of 30% and 15% to 20% and 10%, respectively. The proposals involve a revenue loss of Rs. 30 crores.

96. At present there is a wide dispersion of duty rates among various sectors of the textile industry. My primary aim is to simplify and rationalise the tariff structure and to reduce the duty differential between the various textile fibres and yarns.

97. I propose to rationalise and restructure the excise duty on cotton yarn and cellulosic spun yarn. On cotton yarn, I propose to reduce the multiplicity of rates by having only five duty slabs. Excise duty on cellulosic spun yarn is also being similarly rationalised by having three slabs.

98. I also propose to raise the basic excise duty on viscose filament yarn from Rs. 12 to Rs. 15 per kg., and on acrylic fibre from Rs. 9.24 to Rs. 12 per kg. The duty rates on polyester blended yarns are also being rationalised.

99. Rags and synthetic waste are both raw materials for the shoddy woollen industry. I propose to equate the import duty incidence on both at 110%.

100. With a view to raising the revenue from additional excise duty the proceeds of which go to the States, I propose to increase the duty on processed cotton fabrics by restructuring the duty slabs.

101. Several units in the nylon and polyester filament yarn industry are passing through difficult times. As a measure of relief, I propose to reduce the excise duty on nylon filament yarn from Rs. 63 to Rs. 55 per kg. also to reduce the import duty on caprolactum from 80% to 50%. I also propose to reduce the excise duty on polyester filament yarn from Rs. 70 to Rs. 62 per kg.

102. To promote use of jute by the handloom sector, I propose to fully exempt jute yarn in hanks from excise duty. Similarly, jute products manufactured in rural areas by registered co-operative societies, women's co-operative, etc. are also proposed to be fully exempted from excise duty.

103. As a measure of relief to the silk industry, I propose to reduce the import duty on raw silk 55% to 30%.

104. The package of proposals relating to the textile industry involve a revenue reduction of about Rs. 25 crores.

105. I would now take up the proposals for rationalisation and additional revenue mobilisation.

106. At present excise duty is levied on *ad valorem* basis on some commodities and at specific others. Over the years for administrative reasons, *ad valorem* duties have been steadily replaced by spe-

cific rates or *ad valorem*-cum-specific rates. *Ad valorem* duties are preferable to specific duties as they ensure buoyancy in revenue on account of increase in prices, and the Chelliah Committee has recommended switching over to *ad valorem* rates for a number of commodities. It has also recommended that where specific rates are retained, the same should be revised every year taking into account the price inflation. I propose to make a modest beginning by switching over to the *ad valorem* mode of levy where feasible.

107. In respect of major non-ferrous metals, namely, copper, lead and zinc and products thereof, I propose to fix a uniform *ad valorem* levy of 10% in the place of existing specific rates of duty. As regards iron and steel, the excise duty on primary and semi-finished forms thereof is generally charged at specific rates of duty. For administrative reasons, I propose to retain the specific rates of excise duty on items like ingots and certain rolled products like bars, rods, etc., other than of stainless steel. In respect of these products, I propose to raise the existing rates, which are presently between Rs. 300 and Rs. 1800 per metric ton to rates between Rs. 400 and Rs. 2000 per metric ton. However, in respect of iron forging and other steel products, I propose to prescribe a uniform excise duty of 10%. The proposals involve a revenue gain of about Rs. 400 crores.

108. In my budget speech last year, I mentioned that every Finance Minister has to do his bit to curb smoking which is injurious to health. This injury to health is continuing and I would be failing in my duty if I did not make one more attempt to use the fiscal instrument in this worthy cause. While I do not propose to increase the duty on non-filter cigarettes of less than 60 mm in length, the duties on all other cigarettes are being raised by Rs. 30 to Rs. 100 per thousand depending on the length. The gain in revenue from the proposals is of the order of Rs. 325 crores.

109. I propose to increase the excise duty on certain plastic resins, namely, polystyrene, low density polyethylene, high density polyethylene and polypropylene from 30% to 40%. The revenue gain from the proposals is Rs. 165 crores.

110. Watches attract a very low rate of duty of 5% which is out of line with the general duty structure. I propose to raise the rate of 10%. The revenue gain from the proposal is estimated to be Rs. 12 crores.

111. I propose to increase the excise duty on cement from Rs. 215 to Rs. 290 per metric ton. The excise duty on cement produced in mini cement plants will also go up from Rs. 96 to Rs. 165 per metric ton, thus maintaining the existing duty differential of Rs. 125 per metric ton in favour of mini cement plants. However, I propose to reduce the duty on white cement from 40% to 35% to bring the incidence closer to that on ordinary cement. The estimated revenue gain from these proposals is Rs. 376 crores.

112. I propose to raise the excise duty on paints from the existing levels of 15% and 30% to 20% and 35% respectively. The revenue gain on account of the proposal is estimated to be Rs. 35 crores.

113. I propose to increase the excise duty on organic surface active agents from 25% to 30%. The proposal would yield an additional revenue of Rs. 50 crores.

114. At present two-wheelers such as motorcycles and scooters attract excise duty in slabs of 10%, 15%, 20%, 25% and 30% depending on the engine capacity. I propose to rationalise the duty structure by levying a uniform duty of 15% on all two-wheelers of engine capacity upto 75 cc and 25% on all others whose engine capacity exceeds 75 cc. I also propose to increase the excise duty on light commercial vehicles from 10% to 15%. The proposals involve a revenue gain of Rs. 80 crores.

115. I propose to increase the excise duty on cocoa and cocoa based preparations from 15% to 25%. The proposals involve a revenue gain of Rs. 24 crores.

116. I propose to increase the excise duty on wires and cables by five percentage points from the present levels. The additional revenue from the proposal is expected to be of the order of Rs. 60 crores.

117. I also propose to revise upwards the existing specific rates of excise duty on tyres, tubes and flaps. However, I propose to reduce the duty on moped tyres from Rs. 30 to Rs. 25 per tyre. The proposals involve a revenue gain of Rs. 40 crores.

118. Special excise duty is being levied at present at the rate of 10% of the basic excise duty; certain essential items such as tea, coffee, sugar, matches, kerosene and vanaspathi are fully exempted. In addition, high speed diesel oil and two wheelers attract special excise duty at 5%. I now propose to raise the special excise duty on products which are presently attracting a 10% rate of duty to 15%. However, this increase will not be applicable to petroleum products. I also propose to exempt from this increase certain consumer durables like motor cars and consumer electronics such as television sets, as these industries are passing through a difficult phase. This proposal involves a revenue gain of Rs. 1025 crores.

119. The changes in rate policy introduced last year have eliminated the differential incentives for export at higher stages of manufacture. While a

uniform pattern of incentive is generally to be preferred, there is a case for introducing some disincentives for exports of certain primary products where the same product can be easily exported in value added form. I propose to impose an export duty of 10% on exports of certain types of finished leather and on unpolished granite in order to encourage exporters to shift to leather products and polished granite. I am also imposing an export duty of 5% on iron ore. The proposals are expected to yield an additional revenue of Rs. 142 crores.

120. I have also proposed certain amendments in the Finance Bill seeking to effect changes in the excise and customs tariff. These amendments are generally enabling provisions and have no revenue significance. Besides, there are proposals for amendment of some of the existing notifications. In order to save the time of the House, I do not propose to recount them.

121. The proposals with regard to changes in excise duty outlined above are likely to yield additional revenue of Rs. 2515.70 crores. The concessions and reliefs announced aggregate to Rs. 304.80 crores. Out of the net additional sharable revenue from excise duties of Rs. 2210.90 crores, the Centre's share would be Rs. 1146.53 crores and the States' share Rs. 1064.37 crores.

122. The net impact of my proposals on customs and excise duties taken together amount to an additional mobilisation of only Rs. 187.55 crores on indirect taxes. Since the loss in customs duties falls entirely on the Centre whereas the gain in excise revenue is shared with the States the impact on the Centre's revenue is a loss of Rs. 876.82 crores while the States will gain as much as Rs. 1064.37 crores.

123. Copies of notifications giving effect to the changes in customs and excise duties effective from the 1st March, 1992, will be laid on the Table of the House in due course.

124. Taking direct and indirect taxes together the changes I have proposed are expected to result in a net revenue loss of Rs. 517 crores to the Centre while the States will gain Rs. 1500 crores. Consequently the estimated year end budget deficit of the Centre for 1992-93 will be Rs. 5389 crores and the fiscal deficit for that year will be Rs. 34408 crores.

125. Our nation will remain eternally grateful to Jawaharlal Nehru for his vision and insistence that the social and economic transformation of India had to take place in the framework of an open society, committed to parliamentary democracy and

the rule of law. India's development is of tremendous significance for the future of the developing world. To realise our development potential, we have to unshackle the human spirit of creativity, idealism, adventure and enterprise that our people possess in abundant measure. We have to harness all our latent resources for a second industrial revolution and a second agricultural revolution. Our economy, polity and society have to be extraordinarily resilient and alert if we are to take full advantage of the opportunities and to minimise the risks associated with the increasing globalisation of economic processes. We have to accept the need for reform if we are to avoid an increasing marginalisation of India in the evolving world economy. The economic policy changes brought about by our Government in the last eight months are inspired by this vision. Our party is an inheritor of great

traditions of national service. True to this heritage, we commit ourselves to providing a firm and purposeful sense of direction to the reform process so that this ancient land of India regains its glory and rightful place in the comity of nations. This budget represents a contribution to the successful implementation of this great national enterprise, of building an India free from the fear of war, want and exploitation, an India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realise those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen.

126. Sir, I commend the Budget to this august House.

Smt. JANAKI KAIHPALIA, Addl. Secy. (Budget)